● वर्ष-2
● अंक-289
रायपुर, बुधवार 26 जुलाई 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmail.com

इन दिनों

✍ अमित शर्मा

इंडिया को बेअसर करने भाजपा की रणनीति

बेंगलुरु बैठक में जब विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया (ढ्ढ.ह्न.ष्ठ.ढ्ढ..) रखा था, तब अचानक भाजपा बैकफुट पर आती दिखाई पड़ी थी। उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इस नाम का मुकाबला कैसे करेगी? जिस नाम पर स्वयं केंद्र सरकार ने दर्जनों योजनाएं शुरू कर रखी हों, उसका विरोध वह कैसे करेगी। विरोध करने पर जनता के बीच यह गलतफहमी पैदा होने की संभावनाएं ज्यादा थी कि कहीं वह देश का ही विरोध तो नहीं कर रही है। विपक्ष भी अपने इस हमले को अचूक मान रहा था। उसे लग रहा था कि उसके इस तीर का भाजपा के पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर मचे हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा को इस असमंजस से निकाल लिया है। पार्टी सांसदों की बैठक के बीच उन्होंने बताया कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम रखकर देश को लूटा गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (स्ढ्ढरूढ्ढ) और इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठन अपने नाम में इंडिया शब्द का उपयोग करने के बाद भी देश विरोधी काम करते रहे और इन पर प्रतिबंध लगाया गया। मोदी के बयानों से अब यह साफ है कि आने वाले दिनों में भाजपा विपक्षी दलों के गठबंधन को इन्हीं नामों के साथ जोड़कर हमला करेगी और उसकी विश्वसनीयता कम करने की रणनीति अपनाएगी। प्रचार युद्ध में 2014 से ही बार-बार अपनी काबिलियत दिखा चुकी भाजपा इसको लेकर आक्रामक रुख अपनाएगी और उसे इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आइडिया विपक्ष के इंडिया नाम के असर को बेअसर कर सकेगा? भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता ने कहा कि छद्म नाम रखकर लोगों को भ्रम में डालने की रणनीति आज की तारीख में संभव नहीं है। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के जमाने में लोग बेहद महत्त्वपूर्ण सूचनाओं से लैस हैं। ऐसे में केवल इंडिया शब्द का उपयोग कर विपक्ष जनता को भ्रम में नहीं डाल सकता। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने कहा कि इंडिया शब्द का उपयोग कर विपक्ष ने मोदी पर अचूक हमला किया है। उसे अब तक यह समझ नहीं आ रहा है कि वह इस हमले का मुकाबला कैसे करे। उन्होंने कहा कि आम जनता इस इंडिया शब्द के पूर्ण नाम को कभी नहीं समझने की कोशिश करेगी। उसे इसमें केवल इंडिया दिखाई पड़ेगा और लोग इसे देश से जोड़कर देखेंगे। लेकिन भाजपा जब इस पर हमला करने की कोशिश करेगी, तो उसका नकारात्मक अर्थ निकल सकता है। इस डर से भाजपा में विपक्ष पर हमला करने में हमेशा दुविधा बनी रहेगी। विपक्ष को इस स्थिति का लाभ मिल सकता है। केंद्र के हमलों को देखने के बाद अब उन्हें लगता है कि भाजपा इस हमले का जवाब नहीं खोज पाई है।

संसद में प्रधानमंत्री के बयान पर अड़ा विपक्ष

संसद के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। मणिपुर को लेकर आज भी विपक्षी दलों का जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। हंगामे के बीच ही सरकार की ओर से कुछ कामकाज भी किए गए हैं। लोकसभा में विपक्षी दलों का एक ओर हंगामा हो रहा था वहीं दूसरी ओर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बहु राज्य सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक 2022 को पेश किया और इस पर चर्चाओं का जवाब भी दिया। शाह ने कहा कि हम इस साल विजयादशमी या दिवाली से पहले एक नई सहकारी नीति लाएंगे। राज्यसभा में मणिपुर का मुद्दा उठा। लोकसभा ने बहु राज्य सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दी। विपक्षी दलों ने एक सुर में मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगा। हालांकि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से मणिपुर पर चर्चा होगी उसी तरीके से बंगाल और राजस्थान को लेकर भी चर्चा होनी चाहिए। दूसरी ओर गतिरोध को खत्म करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से एक बैठक बुलाई गई थी।

मणिपुर मामले के चलते हंगामें के बीच दोनों सदनों में हुए थोड़े कामकाज

छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विधेयक राज्यसभा में पारित, विपक्ष ने किया वॉकआउट

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र काफी हंगामे के बीच गुजर रहा है। दोनों सदनों में विपक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। इस बीच राज्यसभा में मंगलवार को छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विधेयक पारित कर दिया। विधेयक पर चर्चा के दौरान मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। लोकसभा ने दिसंबर 2022 में इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी।

राज्यसभा ने छत्तीसगढ़ में धनुहार, धनुवार, किसान, सौंरा, साओंरा और बिंझिया समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने वाले संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी। राज्यसभा में इस विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित किया गया। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022 को चर्चा और पारित कराने के लिए पेश किया।मणिपुर से जुड़े वीडियो जारी होने के बाद विपक्ष केंद्र सरकार पर खासा हमलावर है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार से और पीएम मोदी से सदन में बोलने की मांग कर रहा है। हंगामा के बीच विपक्षी सदस्यों ने बिल का विरोध किया और सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का माइक बंद कर दिया गया और उन्हें अपनी बात पूरी नहीं करने दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने मणिपुर मुद्दा उठाते हुए कहा कि वह विधेयक का समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में आना चाहिए और पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा पर बोलना चाहिए, जिस पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा कि सदन के नेता के उकसावे पर बार-बार बाधा डालने और हंगामे में विधेयकों को पारित करने की जिद के कारण 'इंडिया' के सभी सांसदों ने पूरे दिन सदन से वॉकआउट किया।

मणिपुर के मुद्दे पर लंबी चर्चा को तैयार: शाह

मणिपुर को लेकर संसद में जारी गतिरोध के बीच एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार चर्चा को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। अमित शाह ने बताया कि उन्होंने चर्चा को लेकर लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी भी लिखी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा, यह पता नहीं। सरकार को किसी मुद्दे पर डर नहीं है जिसको जो करनी है कर ले। जनता सब कुछ देख रही है। सरकार मणिपुर मामले पर विस्तार से चर्चा चाहती है। चर्चा के लिए सदन में उचित माहौल होना जरूरी है। संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा के लिए उचित माहौल बेहद जरूरी है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विपक्ष की एक ही मांग है कि प्रधानमंत्री खुद आकर चर्चा की शुरूआत करें। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब मणिपुर के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई थी, उस समय पीएम का मुद्दा था ही नहीं। उन्होंने कहा कि उसके बाद सदन के नेताओं की सर्वदलीय बैठक हुई। उसमें भी उन्होंने (विपक्ष) तत्काल चर्चा की मांग की। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे थे और उन्होंने अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में इस प्रस्ताव को रखा कि मणिपुर संबंधित घटनाओं पर वे चर्चा चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं। आंतरिक सुरक्षा का दायित्व गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आता है।

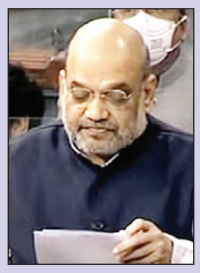

आदिवासी बच्ची पर दुष्कर्म, कवासी लखमा से मांगा इस्तीफा

रायपुर। शनिवार की रात एर्राबोर में पोटा केबिन में आदिवासी नाबालिग छात्रा के दुष्कर्म की घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के सुकमा जिला अध्यक्ष धनीराम बारसे ने विज्ञप्ति जारी कर कोंटा के विधायक एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा के इस्तीफा की मांग की है। धनीराम बारसे का कहना है कि सुकमा जिला में इस प्रकार एक महीना के अंदर-अंदर नाबालिक बच्ची पर दुष्कर्म का यह दूसरा मामला है। और तो और पोटा केबिन की अधीक्षिका ने इस मामले को दबाने का कोशिश किया। शनिवार रात को हुए मामले को दबाने का कोशिश किया गया। और उसी अधीक्षिका को प्रार्थी बना कर रिपोर्ट दर्ज किया जा रहा है। जबकि अधीक्षिका पर एफ आई आर दर्ज होनी चाहिए परंतु कांग्रेस

के स्थानीय विधायक के श्रेय से उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अधीक्षिका कांग्रेस के स्थानीय नेता की बहन भी है इसलिए उसके ऊपर सिर्फ अनौपचारिक कार्यवाही किया जा रहा है।

स्थानीय लोगों के अनुसार अधिकक्षा का पति भी उस पोटा केबिन में आना-जाना करता था एवं रात भी बिताता था। सुकमा का कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि इस भयानक मामले में अब तक गिरफ्तारी न होना किसी घोर आश्चर्य से कम नही। श्री बारसे ने कहा कि पोटा केबिन के अंदर भी बच्ची सुरक्षित नहीं।

धनीराम बारसे ने कहा कि पोटा केबिन अधीक्षक के पद पर कवासी लखमा के इशारे पर मोटी कमीशन वसूल करके नाकाबिल लोगों की नियुक्तियां की जा रही है। मोटा कमीशन देने की एवज में कांग्रेस सरकार के द्वारा कवासी लखमा के इशारे पर पूरी तरह से छूट दी जा रही है। इसी का परिणाम है कि इस तरह के दुष्कर्म की घटना सामने आई है। इसीलिए स्थानीय मंत्री कवासी लखमा को इस्तीफा देना चाहिए। उन्हें अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। जवाबदेही से बचने के लिए कवासी लखमा के पुत्र हरीश कवासी सोशल मीडिया के ग्रुप से तत्काल लेफ्ट हो गए। हर मुद्दे पर राजनीति करने वाले कांग्रेस के नेता इस घटना पर प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं।

धनीराम बारसे ने कहा कि एर्राबोर पोटा केबिन में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं एवं उनके पालक इतने भयभीत हैं कि अपनी बच्चियों को इस पोटा केबिन से वापस घर ले जा रहे हैं। सरकार की व्यवस्था पर उनको यकीन नहीं है। रिपेयरिंग के नाम से अनाप-शनाप खर्चा करने वाले शिक्षा विभाग में पोटा केबिन की हालत बद से बदतर है। जिससे दुष्कर्म करने वाला अपराधी आसानी से आ जा रहा है। शासन की घोर लापरवाही है। पोटा केबिन में पढ़ने वाली बच्चियां सुरक्षित नहीं है।

रायपुर। हरेली तिहार के दिन शुरू हुए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के दूसरे चरण जोन स्तर की शुरूआत 26 जुलाई से हो रही है। इसमें 8 राजीव युवा मितान क्लब को मिलाकर 01 जोन बनाया गया है। जोन स्तर की इस प्रतियोगिता का समापन 31 जुलाई को होगा। पहले चरण में राजीव युवा मितान क्लब स्तर की प्रतियोगिता ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में 17 जुलाई से 22 जुलाई तक आयोजित की गई थी।

प्रमुख समाचार

बैलेंस ऑफ पावर बनने पर ही सरकार में शामिल होने पर विचार करेंगे: मायावती

लखनऊ। मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि चुनाव के बाद बैलेंस ऑफ पावर बनने पर ही सरकार में शामिल होने का विचार किया जा सकता है। वह दिल्ली में मध्य प्रदेश के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ले रही थीं। मायावती इन दिनों लगातार उन राज्यों के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लें रही हैं जहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान के बाद उन्होंने मंगलवार को मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि कर्मठ व ईमानदार उम्मीदवारों का ही चयन किया जाए। कई राज्यों में शक्ति का संतुलन बनने के बावजूद जातिवादी तत्वों द्वारा साम, दाम, दंड, भेद के हथकंडे अपनाए जाते हैं इससे जनता के साथ विश्वासघात कर घोर स्वार्थी लोग सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। इसलिए आगे इन विधानसभा चुनाव में बैलेंस ऑफ पावर बनने पर लोगों की चाहत के हिसाब से सरकार में शामिल होने पर विचार किया जाएगा।

मणिपुर में शर्तों के साथ ब्रॉडबैंड सेवा बहाल, इंटरनेट भी रहेगा बंद

नईदिल्ली। भाजपा के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार ने मंगलवार को ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के निलंबन को उदार तरीके से सशर्त हटाने का आदेश दिया। राज्य के गृह विभाग ने एक आदेश में कहा कि विशिष्ट शर्तों और उपयोगकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक शपथ पत्र के साथ मंगलवार को मणिपुर में ब्रॉडबैंड सेवाएं फिर से शुरू कर दी गईं। मैतेई समुदाय की एसटी दर्जे की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किए जाने के बाद 3 मई को हिंसा भड़क उठी थी। बहुसंख्यक मैतेई समुदाय और अल्पसंख्यक कुकी जनजाति के बीच बढ़ते जातीय संघर्ष के जवाब में सरकार द्वारा बंद किया गया था। हिंसा प्रभावित राज्य में 80 दिनों से अधिक समय तक इंटरनेट बंद रहने के बाद मंगलवार को इंटरनेट आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया। आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय 3 मई से इंटरनेट सेवाओं पर लगातार प्रतिबंध की समीक्षा के बाद आया, जिसने कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सुविधाओं और ऑनलाइन नागरिक-केंद्रित सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया था।

खफा भाजपा व विहिप तलाश रहे कानूनी विकल्प

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने मंगलवार को कहा कि वे हिंदू देवता के बारे में कथित तौर पर विवादित बयान देने को लेकर केरल विधानसभा के अध्यक्ष ए.एन शमसीर के खिलाफ कानूनी उपाय तलाश रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के इरादे से ये टिप्पणियां की गईं। भाजपा और विहिप पिछले सप्ताह राज्य के एर्नाकुलम जिले में एक सरकारी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम 'विद्या ज्योति' में की गई विधानसभा अध्यक्ष की कथित तौर पर विवादित टिप्पणी से आक्रोशित हैं। शमसीर ने कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण में केंद्र सरकार पर बच्चों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बजाय हिंदू पौराणिक कथाएं पढ़ाने का आरोप लगाया था। पार्टी की केरल इकाई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भाजपा की राज्य समिति के एक सदस्य ने तिरुवनंतपुरम पुलिस आयुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराकर अध्यक्ष की कथित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है।

ज्ञानवापी मामला: सुनवाई पूरी, 28 अगस्त को होगा फैसला

नईदिल्ली। ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मंदिर भूमि स्वामित्व विवाद से संबंधित कई याचिकाओं में पक्षों से कुछ स्पष्टीकरण मांगने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज मामले में सुनवाई पूरी की और मामलों पर फैसला सुनाने की तारीख 28 अगस्त तय की। न्यायालय के समक्ष दायर याचिकाओं में वाराणसी अदालत के समक्ष दायर एक मुकदमे की स्थिरता को चुनौती भी शामिल है, जिसमें उस स्थान पर एक मंदिर की बहाली की मांग की गई है जहां ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है। पीठ के समक्ष एक और याचिका अंजुमन मस्जिद समिति ने वाराणसी कोर्ट के 2021 के आदेश को चुनौती दी है। मस्जिद परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि 17 वीं शताब्दी में ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण के लिए एक हिंदू मंदिर को आंशिक रूप से तोड़ा गया था या नहीं। गौरतलब है कि वाराणसी न्यायालय के समक्ष लंबित मामले की कार्यवाही पर सितंबर 2021 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी, साथ ही एएसआई सर्वेक्षण आदेश पर भी प्रभावी रूप से रोक लगा दी।

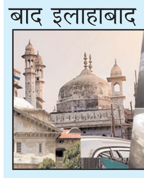

जड़े काट रही सेना! आतंकवादियों के 2 सहयोगी गिरफ्तार

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की जड़ों को काटने के लिए लंबे समय से ऑपरेशन चल रहा है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को खत्म करने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर कश्मीर में सेना की टुकड़ियां चप्पे-चप्पे की जांच कर रही हैं। जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकवादियों के दो सहयोगियों को मंगलवार को गिरफ्तार किया। पुलिस प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने बताया, ''सुरक्षा बलों ने क्रीरी बारामूला के चक टप्पर गांव से लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकवादियों के दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से हथियार, गोला-बारूद व अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की।'' चक टप्पर गांव में आतंकवादी गतिविधियों के बारे में सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा, ''पुलिस ने सुरभा बलों के साथ मिलकर चक टप्पर के बस स्टॉप पर वाहनों की जांच शुरू की। इस दौरान उन्हें दो संदिग्ध देखे। जब उन्हें रुकने का इशारा किया गया, तो वे भागने लगे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया।'' प्रवक्ता के अनुसार, तलाशी के दौरान दोनों संदिग्धों के कब्जे से दो चीनी पिस्तौल, पिस्तौल की दो मैगजीन, 14 जिंदा कारतूस, हथियार और गोला-बारूद सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई।

हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन की रिपोर्ट

17.50 लाख भारतीय कहां गए? हर साल एक लाख से ज्यादा छोड़ रहे देश

नई दिल्ली। पिछले 13 साल के अंदर (2011 से 2023 तक) 17.50 लाख लोगों ने भारत की नागरिका छोड़ दी है। ये लोग विदेशों में जाकर बस चुके हैं। इसको लेकर हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023 भी आ चुकी है। इसमें भी भारत छोड़ने वाले नागरिकों का पूरा ब्योरा दिया गया है।

पाकिस्तान, बांग्लादेश तक की नागरिकता ले रहे लोग

केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने 135 देशों की सूची जारी की है, जहां इन 17.50 लाख से ज्यादा लोग गए हैं। हैरानी की बात है कि भारत की नागरिकता छोड़कर कई लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल और चीन तक की नागरिकता ले चुके हैं। भारत छोड़ने के बाद सबसे ज्यादा लोग अमेरिका में बसे हैं। इनकी संख्या करीब सात लाख बताई जा रही है। इसके अलावा ब्रिटेन, रूस, जापान, इस्राइल, इटली, फ्रांस, यूएई, यूक्रेन न्यूजीलैंड, कनाडा, जर्मनी जैसे देशों में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। कुछ लोगों ने युगांडा, पापुआ न्यू गिनी, मोरक्को, नाइजीरिया, नॉर्वे, जाम्बिया, चिली जैसे देशों की नागरिकता भी ली है।

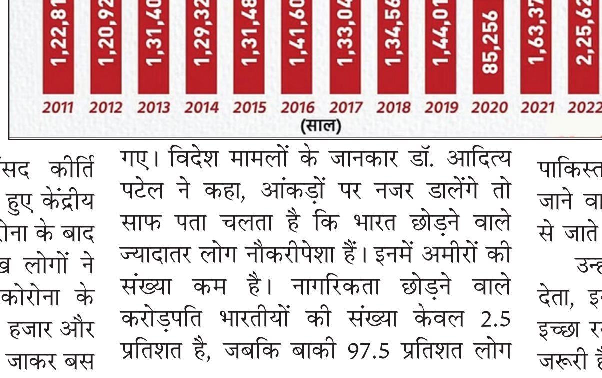

मानसून सत्र के दौरान सांसद कीर्ति चिदंबरम के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना के बाद 2022 में सबसे ज्यादा 2.25 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। कोरोना के दौरान यानी 2020 में सबसे कम 85 हजार और 2021 में 1.63 लाख लोग विदेश में जाकर बस गए। विदेश मामलों के जानकार डॉ. आदित्य पटेल ने कहा, आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो साफ पता चलता है कि भारत छोड़ने वाले ज्यादातर लोग नौकरीपेशा हैं। इनमें अमीरों की संख्या कम है। नागरिकता छोड़ने वाले करोड़पति भारतीयों की संख्या केवल 2.5 प्रतिशत है, जबकि बाकी 97.5 प्रतिशत लोग नौकरीपेशा से हैं। डॉ. आदित्य के अनुसार, भारत की नागरिकता छोड़ने वाले 90 से 95 प्रतिशत लोग बेहतर कॅरियर विकल्प के लिए विदेशों में बसते हैं। कई लोग छोटे देश इसलिए चुनते हैं, ताकि वहां जाकर वह व्यापार कर सकें। इन देशों में टैक्स का दायरा भी कम होता है। इससे उन्हें कारोबार बढ़ाने का अच्छा मौका मिल जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों में जाने वाले ज्यादातर लोग अपने निजी कारणों से जाते हैं।

उन्होंने कहा, भारत दोहरी नागरिकता नहीं देता, इसलिए किसी दूसरे देश में बसने की इच्छा रखने वाले लोगों को नागरिकता छोड़नी जरूरी है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में विदेश छोड़ने वालों के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। 2010 तक नागरिकता छोड़ने वाले सात प्रतिशत की सालाना दर से बढ़ रहे थे। अब यह दर 29 फीसदी हो गई है।

भारतीय लोगों को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है?

संसद में केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने कहा, %ज्यादातर लोग काम के सिलसिले में विदेश जाते हैं और वहां व्यक्तिगत सुविधाओं के चलते रहने लगते हैं। ऐसे में भारतीयों के पलायन को रोकने के लिए सरकार कई तरह से कदम उठा रहा है। मेक इन इंडिया के जरिए भारत में ही नागरिकों को बेहतर कॅरियर का विकल्प देने की कोशिश हो रही है। इसका असर भी हो रहा है।

कितने लोगों ने नागरिकता छोड़ी है?

2011	1,22,819
2012	1,20,923
2013	1,31,405
2014	1,29,328
2015	1,31,489
2016	1,41,603
2017	1,33,049
2018	1,34,561
2019	1,44,017
2020	85,256
2021	1,63,370
2022	2,25,620
2023	87,026

नोट : 2023 के आंकड़े 26 जून तक के हैं।

मानसून सत्र में विधायक रंजना ने दागे जनहित मुद्दों के अनेक सवाल

■ शून्यकाल में उठाया रेल्वे प्रभावित औद्योगिक वार्ड के व्यवस्थापन एवं मिलरों के कस्टम मिलिंग अनुबंध का मुद्दा

धमतरी। विधानसभा में अपनी मुखरता से निरंतर जनहित के मुद्दों को सदन पर पूरी परिपक्वता से विधायक रंजना डीपेंद्र साहू रखती आई है, पंचम सत्र के अंतिम सत्र में विधायक रंजना साहू ने क्षेत्र के अनगिनत मुद्दों को विधानसभा पटल पर रखी और बड़ी ही मुखरता से तारांकित प्रश्न, आतारांकित प्रश्न, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल, याचिका के द्वारा कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। विधानसभा सत्र के दरमियान शून्यकाल के अंतर्गत रेलवे से प्रभावित औद्योगिक वार्ड के व्यवस्थापन का मुद्दा उठाई, विधायक ने कहा कि नगर निगम के द्वारा नोटिस जारी की गई है किंतु आज पर्यंत तक औद्योगिक वार्ड के लगभग 300 से अधिक परिवारों को व्यवस्थापन नहीं किया गया है और नोटिस जारी किया जाना अनुचित है, इसके साथ साथ ही मिलरों को सरकार के द्वारा कस्टम मिलिंग अनुबंध के तहत पर्याप्त मात्रा में धान उपलब्ध नहीं कराए जाने, समय पर बारदाने कि उपलब्धता पूरा नहीं कर पाने के कारण मिलरों से अनुबंध पूरा नहीं हो पाया जिसके लिए सरकार द्वारा अतिरिक्त पेनल्टी लगाई गई जो सर्वथा अनुचित है। अंतिम सत्र में विधायक रंजना डीपेंद्र साहू ने प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं आवास प्लस योजना के पात्र हितग्राहियों की

जानकारी जिलेवार मांगी जिसमें आज भी 16 लाख से अधिक पात्र हितग्राही इस योजना के लाभ नहीं उठा पाए हैं और राज्य सरकार के उदासीनता के चलते इन सभी 16 लाख परिवारों को आवाज से वंचित होना पड़ा है। इसी तरह विधायक ने नगर पालिक निगम धमतरी एवं नगर पंचायत आमदी द्वारा गो-धन न्याय योजना अंतर्गत खरीदी के संबंध में नगरी प्रशासन मंत्री से प्रश्न किए, समूह द्वारा संचालित गोबर खरीदी एवं वर्मी कम्पोस्ट खाद की जानकारी मांगी गई जिस पर समुचित जानकारी विभागीय मंत्री द्वारा नहीं दिया गया जिसमें स्वयं सहायता समूह के राशि आज तक पूरी नहीं मिल पाई है।छत्तीसगढ़ शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के प्रकरण की जांच पर चिकित्सा शिक्षा विभाग पर प्रश्न करते हुए विधायक ने पूछा कि प्रकरण की उससे उच्च स्तरीय छानबीन एवं फर्जी जाति प्रमाण के संबंध में सवाल किए जिस पर उपमुख्यमंत्री ने 20 जून 2023 की स्थिति में उच्च स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रकरण को विचाराधीन बताया गया। खेलो इंडिया के तहत छत्तीसगढ़ को प्राप्त राशि पर उच्च शिक्षा मंत्री को प्रश्न करते हुए विधायक ने छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेल की जानकारी मांगी गई जिसमें खेल एवं युवा कल्याण विभाग में छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल योजना संचालित नहीं होने का उत्तर मिला। इसी तरह विधायक ने विधानसभा पटल पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत रिक्त पद, छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2030 अभियान का उद्देश्य, धमतरी जिले में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति, सिंचाई सुविधा विस्तार जीर्णोद्धार कार्य एवं बजट में शामिल कार्यों की जानकारी का प्रश्न, धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित शासकीय उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में संचालित भवन की जानकारी, स्नातकोत्तर की कक्षाएं, औद्योगिक केंद्र भटगांव में नए पाठ्यक्रम का शुरू करने का प्रश्न विधानसभा सत्र में लगाई।

छत्तीसगढ़ में परिवर्तन को लेकर आप की बदलाव पदयात्रा

कोरबा। चुनावी बिगुल बज चुका है और आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी तैयारी में है स जनता का ध्यान आकर्षण वह दिल्ली पंजाब में हो रहे विकास कार्यों व जनकल्याणकारी कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पूरे प्रदेश में बदलाव पदयात्रा की शुरुआत की है। इसी कड़ी में कोरबा जिले में विधानसभा वार बदलाव पदयात्रा की शुरुआत हो गई है स कोरबा यूथ विंग जिला अध्यक्ष अमर चौहान व जिला सचिव नियाज खान के नेतृत्व में बाइक रैली का आयोजन किया गया। जिसकी अगुवाई प्रदेश यूथ विंग अध्यक्ष रविंद्र सिंह व प्रदेश सचिव विशाल केलकर ने की स बाइक रैली सुभाष चौक से सुनालिया चौक तक निकाली गई और सुनालिया चौक से पुराना बस स्टैंड तक बदलाव यात्रा निकाल निकाली गई। जिसमें सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता व गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इसी तरह पाली-तानाखार के पसान में प्रदेश सह प्रभारी नरेश बारिया, विधानसभा प्रभारी प्रितपाल शर्मा, जिला अध्यक्ष चंद्रकांत डिकसेना, जिला सचिव शत्रुघन साहू की अगुवाई में बदलाव पदयात्रा निकाली गई। यहां भी पदयात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिला,अपने उद्बोधन में नरेश बारिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता पूरे 23 साल का हिसाब मांग रही है। कांग्रेस व

भाजपा की सरकार ने जनता को गुमराह कर केवल अपना स्वार्थ सिद्ध की है। इस बार छत्तीसगढ़ की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का मूड बना लिया है। जिला विधानसभा प्रभारी प्रितपाल शर्मा ने कहा कि लोग अपने परिवार की खुशहाली के लिए आम आदमी पार्टी की ओर आशावान नजर से देख रहे है । छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो जीरो बिजली बिल बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सहित बुनियादी सुविधाओं की गारंटी है। पीढ़ी बदलनी है तो आम आदमी को वोट जरूर दीजिए। विषय पर प्रदेश सचिव विशाल केलकर ने बताया कि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की सरकार से त्रस्त हो चुकी है, सरकार ने अपने साढ़े 4 साल के कार्यकाल में जनता से किये कई वायदे अभी तक पूरे नही किये, जिसमे बिजली, सड़क, शिक्षा, महिला सुरक्षा रोजगार, कर्मचारियों के हक में कोई ठोस कदम ऐसे अनेक मुद्दे है जिस से जनता त्रस्त हो चुकी है और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है।

सुघ्घर पढ़वईया योजना : दो स्कूल प्लेटिनम व सिल्वर अवार्ड के लिए हुए नामित

■ दोनों स्कूल स्वतंत्रता दिवस में राज्य स्तर पर होंगे सम्मानित

रायगढ़। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप जिले के सभी शासकीय प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक स्कूलों में पढने वालों बच्चों में उनकी प्रतिभा के अनुरूप कौशल विकसित करने के लिए सुघ्घर पढ़वईया योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत बच्चों में कौशल विकसित करने पर उत्कृष्ट विद्यालयों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाता है। इसी कड़ी में विकासखण्ड रायगढ़ के प्राथमिक शाला भदरापाली संकुल बायंग को प्लेटिनम अवार्ड एवं प्राथमिक शाला परसाडीपा संकुल डोंगीतराई को सिल्वर अवार्ड हेतु नामित किया गया है। आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उक्त दोनों स्कूलों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।

कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशन में जिले में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। स्कूलों के सभी शिक्षकों को साथ मिलकर स्कूल के सभी विद्यार्थियों में अकादमिक कौशल विकसित करने हेतु कार्य किया जा रहा है। इसी का प्रत्यक्ष परिणाम सामने आया और इन दोनों स्कूलों को प्लेटिनम एवं सिल्वर अवार्ड हेतु नामित किया गया है। जो रायगढ़ जिले के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश स्तर पर उपलब्धि है। कलेक्टर श्री सिन्हा के निर्देश में जिले के अन्य शालाओं में भी शिक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य किया जा रहा है।

सुघ्घर पढ़वईया योजना का उद्देश्य स्वप्रेरणा से अच्छे कार्य एवं बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित

करना है। उन्हें देखकर और भी शिक्षक अच्छे से कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकेंगे। यह योजना राज्य के सभी शासकीय प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों के लिए है। योजना में शामिल होने के लिए स्कूल को वेब-पोर्टल पर आवेदन करना होगा। स्कूलों की प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से नहीं बल्कि स्वयं से ही है। स्कूलों के सभी शिक्षकों को साथ मिलकर स्कूल के सभी विद्यार्थियों में अकादमिक कौशल विकसित करना है। जिन स्कूलों को प्रमाण पत्र मिलेगा, उस स्कूल में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को भी प्रमाण पत्र मिलेगा। प्रमाणीकरण की घोषणा थर्ड-पार्टी आंकलन के तत्काल बाद वेब-पोर्टल पर की जाती है।

रायगढ़ जिले के सात विकासखण्ड धरमजयगढ़, घरघोड़ा, लैलूंगा, तमनार, रायगढ़, खरसिया एवं पुसौर में से 35 शाला का थर्ड पार्टी द्वारा आकलन किया गया। जिसमें 2 शाला अवार्ड हेतु नामित किए गए। जिसमें विकासखण्ड रायगढ़ के प्राथमिक शाला भदरापाली को प्लेटिनम अवार्ड एवं प्राथमिक शाला परसाडीपा को सिल्वर अवार्ड हेतु नामित किया गया है। आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उक्त दोनों स्कूलों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।

राज्य संभल नहीं रहा राष्ट्रीय नेता बनने निकले भूपेश : भाजपा

■ मणिपुर की घटना पर निंदा प्रस्ताव भूपेश सरकार की विशुद्ध राजनीतिक नौटंकी: विकास मरकाम

नगरी। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार द्वारा मणिपुर की घटना पर केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। विकास मरकाम ने कहा मणिपुर राज्य की घटना एक राज्य विशेष की घटना है और स्थानीय घटना है जिस पर केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना ना केवल अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना है बल्कि एक विशुद्ध राजनीतिक नौटंकी भी है।

विकास मरकाम ने भूपेश बघेल से पूछा कि क्या छत्तीसगढ़ में विधानसभा के करीब छत्तीसगढ़ के मंत्रियों की गाड़ी के सामने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओं द्वारा नग्न प्रदर्शन के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? वास्तव में उसके लिए तो छत्तीसगढ़ की भूपेश

सरकार ही जिम्मेदार है जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी लेने वालों के ऊपर मेहरबान बन कर बैठी है और कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

मरकाम ने कहा नग्न प्रदर्शन समूचे भारत में पहली घटना है जिसने छत्तीसगढ़ की संस्कृति सरकार और समूचे जन समुदाय को शर्मसार कर दिया है, भूपेश सरकार के माथे पर यह कभी न मिटने वाला दाग है जिसे धोने के लिए मणिपुर की घटना पर निंदा प्रस्ताव की नौटंकी की जा रही है। भूपेश बघेल से खुद का राज्य संभल नहीं रहा और राष्ट्रीय नेता बनने की महत्वकांक्षी पाल ली है। यही महत्वाकांक्षा भूपेश बघेल को आगामी विधानसभा चुनाव में डुबाने वाली है। जिसके बाद उनके पास पछतावे का भी समय नहीं होगा।

राजेन्द्र गोलछा ने केंद्र सरकार का जताया आभार

नगरी। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं जिला मंत्री राजेंद्र गोलछा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों के करोड़ों रूपये की वापसी का मार्ग प्रशस्त होने पर केंद्र सरकार तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी का धन्यवाद ज्ञापित किया है। गोलछा ने बताया कि सहारा इंडिया के निवेशकों एवं अभिकर्ताओं की समस्याओं का शीघ्र निराकरण की मांग बिलासपुर सांसद अरुण साव ने लोकसभा में रखा था।साव ने लोकसभा में नियम 377 के तहत इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने लोकसभा में कहा था कि छग एवं देश के लाखों लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा सहारा इंडिया के विभिन्न योजनाओं के तहत जमा कराये हैं परन्तु आज वे अपने जमा पैसे को वापस प्राप्त करने के लिए दर दर की ठोकर खाने मजबूर हैं। सहारा ने सेबी के खाते में 24 हजार करोड़ की राशि जमा कर दिया है किंतु निवेशकों को उनकी राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है जिससे निवेशकों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इस विवाद के कारण हजारों अभिकर्ताओं के सामने जीवन यापन का संकट उठ खड़ा हुआ है।

गोलछा ने विज्ञप्ति में कहा कि सांसद अरुण साव के प्रयास से ही आज लाखों निवेशकों का सहारा इंडिया में फंसे करोड़ों

रूपये की राशि वापसी का मार्ग प्रशस्त हुआ है। लोकसभा में निवेशकों की समस्याओं व परेशानीयों को साव ने प्रभावी ढंग से सामने रखा। इसी का परिणाम रहा कि केंद्र सरकार ने राशि वापसी कराने रिफंड पोर्टल का शुभारम्भ किया है। इससे सहारा इंडिया में अपनी गाढ़ी कमाई इन्वेस्ट करने वाले निवेशकों को राहत मिली है। इसके जरिये पैसों की वापसी बेहद आसान होगी और 45 दिनों में निवेशकों को अपना फंसा हुवा रकम मिल जायेगा। इस प्रक्रिया के लिए निवेशकों को किसी एजेंट के पास जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी बल्कि घर बैठे मोबाइल कंप्यूटर से ही आसानी से आवेदन कर सकेंगे। राजेंद्र गोलछा ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के प्रति आभार व्यक्त किया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

बाघ खाल तस्करी के तीन आरोपियों की जमानत खारिज

बीजापुर। इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर के मद्देड बफर क्षेत्र के रुद्रारम से 29 जून को बाघ की खाल के साथ तीन आरोपी पकड़े गए थे, उनकी निशानदेही पर विभाग की कार्रवाई जारी है। बाघ की खाल तस्करी मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों किशोर दशरारिया, धर्मपाल नानाजी चापले और श्यामराव शिवनकर की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में वन विभाग अब तक 39 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुका है, हालांकि सात आरोपी अब भी फरार हैं। पकड़े गए सभी आरोपियों में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के डॉक्टर, मेडिकल स्टोर संचालक और पुलिस के जवान शामिल हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर के डिप्टी डायरेक्टर गणवीर धम्मशील ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जमानत खारिज होने के बाद आरोपियों को 18 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया हैं। आरोपी किशोर दशरारिया निवासी छत्तीसगढ़ को मद्देड के रुद्रारम से पकड़ा गया था, वहीं धर्मपाल व श्यामराव को महाराष्ट्र के चंद्रपुर व गोंदिया से पकड़ा गया था।

रीपा में बने उत्पाद स्कूल पुलिस कैम्पो में होगी आपूर्ति

बीजापुर। चारो विकास खंडो में 2-2 रीपा संचालित है जहां विभिन्न सहायता समूह की महिलाएं एवं उद्यमी अपने-अपने औद्योगिक इकाईयों में उत्पादन को गति

प्रदान कर रहे हैं। कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा एवं जिला सीईओ रवि कुमार साहू के मार्गदर्शन में उत्पादन का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। रीपा से बने घरेलू उत्पाद सामग्री मिर्च, मसाला, हल्दी, धनिया, अचार, पापड़ जैसे खाद्य सामग्री जो कि गुणवत्तापूर्ण निर्मित किया जा रहा है। जिसे स्थानीय बाजार, सी-मार्ट के अलावा स्कूल, आश्रम, पोटाकेबिन सहित पुलिस कैम्पो, आंगनबाडियों में भी आपूर्ति किया जाएगा ताकि समूह की महिलाओ को व्यापक स्तर पर बाजार उपलब्ध हो सके और उत्पादन, विक्रय में वृद्धि के साथ-साथ आजिविका गतिविधियो में बढ़ोतरी हो सके।

रायपुर से बस्तर तक फैला आंखों का संक्रमण

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में तेजी से आई फ्लू या पिंक आई का संक्रमण फैल रहा है। रायपुर से लेकर बस्तर और प्रदेश के अन्य जिलों में इसके मरीज सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा बच्चे इसकी चपेट में हैं। आंकड़ों की बात करें तो औसतन 40 से 50 मरीज रोज मिल रहे हैं। पिछले सात दिनों में रायपुर के आंबेडकर अस्पताल में ही 300 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। वहीं दो दिन में बिलासपुर में 500 और बस्तर में 15 दिनों में 1200 से ज्यादा केस मिले हैं। यह सिर्फ सरकारी आंकड़ें हैं। प्राइवेट अस्पतालों और क्लीनिक में मरीजों का आना जारी है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। बालोद, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और कोरबा सहित अन्य जिलों में स्कूली बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमण की चपेट में हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्कूलों सहित अन्य जगहों पर कैंप लगाया गया है। दुर्ग में विभाग की ओर से खुर्सीपार क्षेत्र के शिवाजी नगर में दो दिन पहले लगाए गए शिविर में दो घंटे के भीतर ही कंजक्टिवाइटिस के 70 से अधिक मरीज पहुंच गए थे।

सोनकर समाज मेहनती समाज : रंजना साहू

धमतरी। धमतरी सोनकर समाज भवन में विधायक की अनुशंसा से स्वीकृत विधायक निधि से 5 लाख के शेड निर्माण का लोकार्पण करने सामाजिक भवन रामबाग विधायक रंजना साहू ने पहुंच कर किए,

उन्होंने ने कहा कि सोनकर समाज एक मेहनती समाज है पहले सोनकर समाज की एक पारंपरिक व्यवसाय सब्जी विक्रेता थी, पर आज ऐसा नहीं है पुराने पीढ़ी के लोग खेती बाड़ी करके सब्जी व्यवसाय करके अपने भविष्य के कर्णधार बच्चों को बहुत पढ़ाया लिखाया है, आज सोनकर समाज एक शिक्षित समाज के रूप में जाना जाता है, सोनकर समाज शिक्षा के साथ-साथ राजनीति में भी और व्यवसाय जगत में भी बहुत आगे हैं। सोनकर समाज से धमतरी नगर से ही लगभग 12 एमबीबीएस डॉक्टर और 4 एमएस सर्जन डॉक्टर है, जो निरंतर समाज की सेवाएं कर रहे हैं, सभी अपने सेवा कार्य मे लगे है ऐसे समाज को विधायक ने मंचपर सादर नमन किए।

मणिपुर हिंसा के विरोध में सर्व आदिवासी समाज का प्रदर्शन

नगरी। हिंसाग्रस्त मणिपुर में कुकी समुदाय की महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने एवं सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में सर्व आदिवासी समाज नगरी की अपील पर बजरंग चौक नगरी में मणिपुर के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर जन आक्रोश रैली निकालकर अनुविभागीय अधिकारी नगरी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया।जिसमें तत्कालीन मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना को बेहद शर्मनाक बताया और दोषियों को तत्काल कड़ी सजा देने की मांग की।इसी प्रकार एमपी के सीधी में हुए पेशाब कांड , इंदौर और मंडला की घटनाओं की निंदा की। प्रदर्शन करने वाले में उमेश देव अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज तहसील नगरी,प्रमोद कुंजाम युवा जिलाध्यक्ष, हेमलाल मरकाम, जोहत नेताम ,मधु नेताम, देव कुमारी ,पूर्णिमा मरकाम, तेज प्रभा मरकाम, नरेश छेदेहा,फलेंद्र यादव, पोखन नेताम, कुशल नेताम ,सिरधन सोम आदि उपस्थित थे।

छात्रावास में बच्चों से कराया जा रहा है काम, परिजनों में नाराजगी

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही। सरकार अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को बच्चों की पढ़ाई और उनके रहने के लिए लाखों रुपए का फंड देती है। बावजूद इसके छात्रावास द्वारा बच्चों से काम कराया जाता है। ऐसा ही एक मामला गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से सामने आया है। जहां कुछ छात्राओं से काम कराया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार पूरा मामला मरवाही ब्लॉक के सेमरदर्री कन्या छात्रवास का है। जहां कुछ छात्राओं को छात्रावास के बाहर पानी लाने को कहा जा रहा है। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। जिसमें देखा जा सकता हैं कि बच्चे कैसे छात्रावास के बाहर से कुछ छात्राएं पानी भरकर ले जा रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद छात्राओं के परिजनों में नाराजगी देखने को मिल रही है। छात्रावास में बच्चों के साथ हो रहे शोषण

पर सवाल उठता है कि बच्चें अपनी पढ़ाई करें या छात्रावास का काम। आपको बता दें कि छात्रावास में सफाई, बर्तन साफ करने, कपड़े धोने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। लेकिन छात्रावास में स्टाफ के नहीं रहने के कारण बच्चों को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

हॉस्टल में खाना-पानी व बिजली की समस्या, बच्चों ने बयां किया दर्द

कांकेर। नरहरपुर विकासखंड में बने हॉस्टल में रह रहे बच्चे परेशान हैं। मंगलवार को कई छात्र स्कूल ड्रेस में कांकेर कलेक्टर ऑफिस पहुंच गए. छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल के अधीक्षक हॉस्टल की समस्याओं को सही नहीं कर रह रहे हैं। भोजन में सब्जी एक ही बार दी जाती है। दोबारा मांगने पर नहीं दी जाती है। छात्रों ने कलेक्टर ऑफिस में प्रभारी सहायक आयुक्त से मुलाकात कर हॉस्टल की समस्याओं की जानकारी दी.

नरहरपुर विकासखंड के बासनवाही गांव में 50 सीटर प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास है। यहां वर्तमान में 26 छात्र रहते हैं। हॉस्टल के छात्र स्कूल ड्रेस के साथ बस से कांकेर पहुंचे। बच्चे सीधे कलेक्टरेट स्थित सहायक आयुक्त कार्यालय पहुंचे। यहां अफसरों से हॉस्टल अधीक्षक रामसिंह केसरा की शिकायत करते हुए हॉस्टल की समस्याएं बतायीं। छात्रों का कहना है कि हॉस्टल भवन की स्थिति अच्छी नहीं है। पानी का रिसाव होता है। 6 कमरों में से 3 कमरों का ही उपयोग हो रहा है। दो कमरों के पंखे बंद पड़े हैं। बाथरूम में पानी नहीं आता है। एक बाथरूम में लाइट तक नहीं है। खिड़कियां टुट चुकी हैं। दरवाजे खराब हो चुके हैं। एक बाथरूम का तो दरवाजा ही गायब हो गया है।

छात्र अखिलेश्वर कोर्राम, दिलशान शोरी, मनीष कोर्राम, देवव्रत वट्टी, दुर्गेश निषाद, जयप्रकाश धुरव, देवव्रत नागेश, प्रियांश मरकाम ने कहा हॉस्टल में सब्जी पर्याप्त मात्रा में नहीं दी जाती है। हॉस्टल अधीक्षक से कहने पर वे ध्यान नहीं देते। प्रभारी सहायक आयुक्त मनीष मिश्रा ने कहा हॉस्टल अधीक्षक के खिलाफ बच्चे शिकायत लेकर पहुंचे थे। हॉस्टल अधीक्षक को बुलाकर हिदायत दी गई है।

12 वर्षों से नक्सली संगठन में सक्रिय नक्सली विस्फोटक के साथ गिरफ्तार

जगदलपुर। मुखबिर से मिली सूचना पर दरभा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोरोपाल की ओर जवान नक्सल सर्चिंग गश्त के लिए निकले थे, इसी दौरान नक्सली हत्या की वारदात में शामिल ग्राम कोरोपाल निवासी नक्सली गंगो कुहरामी पिता मगडू उम्र 40 वर्ष को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से पुलिस ने विस्फोटक सामग्री, जिलेटिन वायर कार्डेक्स वायर, जिलेटिन, डेटोनेटर जब्त किया है। जो विगत 12 वर्षों से नक्सली संगठन में सक्रिय रुप से जुड़कर कई वारदातों में शामिल रहा। थाना दरभा में कार्यवाही उपरांत मंगलवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। गिरफ्तार नक्सली गंगों कुहराम के विरुद्ध कई नक्सल आपराधिक मामले पुलिस थानों में दर्ज हैं, वर्ष 2016 में गंगो कुहरामी अपने अन्य नक्सल साथियों के साथ मिलकर

कापानार निवासी भीमा कवासी और नडेनार निवासी जलनो पोडियामी को साप्ताहिक बाजार पखनार में घेरकर धारदार हथियार से मारकर हत्या किया था। जिसके विरुद्ध हत्या, आर्म्स एक्ट, यूएपीए एक्ट सहित दर्जनों नक्सल मामले में एफआईआर दर्ज हैं। उक्त सभी मामलों में पुलिस के द्वारा लगातार तलाश की जा रही थी।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

केंद्र के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है विपक्षी दल

नईदिल्ली। एक ओर जहां सरकार मणिपुर पर चर्चा को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संसद में एक बड़ा विधायी प्रयास करने की योजना बना रही है। वहीं, दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना पर काम रहा है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। मंगलवार सुबह भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (इंडिया) के घटक दलों की बैठक में नोटिस सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। सूत्रों ने कहा कि सभी दल एक साथ हैं और राज्यसभा के लिए रणनीति बनाई जा रही है। संघर्षग्रस्त मणिपुर की स्थिति पर संसद में बोलने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करने के लिए मजबूर करने का यह एक प्रभावी तरीका होगा।

अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी जेडीएस : एचडी देवेगौड़ा

बेंगलुरु। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने मंगलवार को कहा कि जनता दल (सेक्युलर) लोकसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। नवीनतम निर्णय कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के इस कथन के बाद आया है कि उनकी पार्टी, जद(एस) और भाजपा विपक्ष के रूप में सहयोग करेंगे। देवेगौड़ा ने कहा, जेडी (एस) कार्यकर्ताओं से परामर्श के बाद लोकसभा चुनाव में केवल उन क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारेगी जहां पार्टी मजबूत है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि चाहे हम (पार्टी) पांच, छह, तीन, दो या एक सीट जीतें, हम लोकसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं से विचार-विमर्श के बाद उन्हीं जगहों पर उम्मीदवार उतारेंगे जहां हम मजबूत हैं। अपने बयान में कुमारस्वामी ने कहा था कि मैं विधानसभा में और उसके बाहर पहले ही कह चुका हूं कि चूंकि भाजपा और जद (एस) विपक्षी दल हैं, इसलिए राज्य के हित में मिलकर काम करने का फैसला किया गया है।

बहाल नहीं होगी अफजाल की संसद सदस्यता

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बसपा से पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की याचिका खारिज कर दी है। अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट मामले में निचली अदालत से मिली सजा पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की थी। निचली अदालत से 4 साल की सजा सुनाए जाने के बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी समाप्त हो गई थी। अफजाल की याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि सजा पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है बल्कि अपवाद है जिसका सहारा दुर्लभ मामलों में लिया जाना चाहिए। उच्च न्यायलय के फैसले से साफ हो गया है कि अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी बहाल नहीं होगी और न ही वह आने वाले समय में कोई भी चुनाव लड़ पाएगा। हालांकि गैंगस्टर मामले में 29 अप्रैल को गाजीपुर की अदालत से 4 साल की सजा मिलने के बाद जेल में बंद अफजाल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 24 जुलाई को राहत भी दी थी। हाई कोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में अफजाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी।

त्रिपुरा टीएमसी प्रदेश अध्यक्ष पीजूष कांति ने छोड़ी पार्टी

कोलकाता। त्रिपुरा में ममता बनर्जी की तणमूल कांग्रेस पार्टी को मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी प्रदेश अध्यक्ष पीजूष कांति बिस्वास ने मंगलवार को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए पार्टी भी छोड़ दी है। याद रहे हाल ही में उत्तर पश्चिमी राज्य त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें टीएमसी ने एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं की थी। वहीं चुनाव के महीनों बाद प्रदेश के टीएमसी प्रदेश अध्यक्ष पीजूष कांति बिस्वास ने ममता बनर्जी की पार्टी को ही अलविदा कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमों ममता बनर्जी को पीजूष कांति ने अपना इस्तीफा भेजा है। ममता को भेजे गए इस्तीफा लिखा उसमें पीजूष कांति बिस्वास ने लिखा, मैं त्रिपुरा प्रदेश तृणमूल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद और इसकी प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे रहा हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। इसके साथ ही पीजूष ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को टीएमसी त्रिपुरा का उन्हें अध्यक्ष बनाए जाने का आभार भी व्यक्त किया।

'इंडिया' मणिपुर में भारत की अवधारणा का पुनर्निर्माण करेगा

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) पर निशाना साधे जाने के बाद मंगलवार को उन पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इस गठबंधन को लेकर कुछ भी कहें, लेकिन यह इंडिया है, जो मणिपुर को मरहम लगाने तथा हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेगा। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि यह विपक्षी गठबंधन मणिपुर में भारत की अवधारणा का पुनर्निर्माण करेगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी जी, आप हमें जो चाहें संबोधित कर लें। हम इंडिया हैं। हम मणिपुर को मरहम लगाने और हर महिला एवं बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम राज्य के सभी लोगों के जीवन में प्यार और शांति वापस लाएंगे। हम मणिपुर में भारत की अवधारणा का पुनर्निर्माण करेंगे।

भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने साधा विपक्षी दलों पर निशाना

ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसे विपक्षी दलों ने बनाया 'इंडिया': मोदी

नईदिल्ली। संसद में जारी गतिरोध के बीच मंगलवार को भाजपा के संसदीय दल की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नए नाम इंडिया पर तंज कसा और कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडियन है लेकिन सिर्फ इंडिया नाम रखने से इंडिया नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष हताश और निराश है और उसके आचरण से पता चलता है कि उन्होंने लंबे समय तक विपक्ष में रहने का ही मन बना लिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे नामों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल देश का नाम इस्तेमाल करके ही लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विपक्षी पार्टियों ने इंडिया नाम, लोगों को गुमराह करने के लिए रखा है। विपक्ष, सत्ता में नहीं आना चाहता। लोगों को गुमराह करने के लिए ही इंडिया नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है....विपक्ष दिशाहीन है। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष ने मन बना लिया है कि उन्हें लंबे समय तक विपक्ष में ही रहना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया में भारत की छवि काफी बेहतर हुई है और हम इस दिशा में काम करने के लिए समर्पित हैं। प्रधानमंत्री ने अमृत काल के खत्म होने तक यानी 2047 में तक हम देश को विकसित देश बनाएंगे। देशवासियों को हमसे बड़ी उम्मीदें हैं और विपक्ष ये बात जानता है कि वह सत्ता में नहीं आने वाला। पीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में विपक्ष और टूटेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि लोगों के समर्थन से 2024 के चुनाव में भी भाजपा सत्ता में आएगी। अगले कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सदन में विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए रणनीति बनाने के लिए भाजपा ने संसदीय दल की बैठक

बुलाई थी। इस बैठक में ही पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखे हमले किए।

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमें अपने पीएम पर गर्व है। हम 2024 में सत्ता में वापस आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना विदेशी नागरिकों ने की थी। आज लोग इंडियन मुजाहिदीन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे नामों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये चेहरे कुछ दिखाते हैं और सच्चाई कुछ और है।

मणिपुर जल रहा और प्रधानमंत्री ईस्ट इंडिया की बात कर रहे : खड़गे

नईदिल्ली। संसद में मणिपुर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त तरीके से तकरार है। विपक्षी दल मणिपुर पर चर्चा की मांग पर अड़े हुए हैं। इन सबके बीच राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। खड़गे ने साफ तौर पर कहा है कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। दरअसल मणिपुर में पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से हिंसा जारी है। संसद सत्र से पहले मैच में महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद हंगामा और भी बढ़ गया। विपक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की लगातार मांग कर रहे हैं। इसको लेकर लोकसभा में भी हंगामा मचा हुआ है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज मणिपुर जल रहा है, वहां दुष्कर्म हो रहे हैं। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं और यहां प्रधानमंत्री ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतने सारे प्रतिनिधि संसद में 267 के तहत नोटिस दे रहे हैं। प्रश्नकाल में ही नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मणिपुर की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि इस संबंध में करीब 50 सदस्यों ने नोटिस दिया है। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर मुद्दे पर बोलेंगे। उन्होंने कहा कि हम राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर भी चर्चा चाहते हैं। मणिपुर हिंसा पर चर्चा की विपक्ष की मांग को लेकर मंगलवार को भी राज्यसभा में गतिरोध बना रहा और सरकार ने जोर दिया कि पूर्वोत्तर राज्य के साथ ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए। उच्च सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे शुरू होने पर भी स्थिति पहले जैसी ही रही और विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य मणिपुर हिंसा पर कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा कराने की मांग करने लगे। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जवाब की भी मांग कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रश्नकाल चलाया और कुछ सदस्यों ने पूरक सवाल किए और संबंधित मंत्रियों ने उनके जवाब भी दिए।

गठबंधन बनने से प्रधानमंत्री परेशान 'इंडिया' से नफरत करने लगे हैं

नयी दिल्ली। विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) के घटक दलों ने मंगलवार को आरोप लगाया कि विपक्ष का यह मोर्चा बनने से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परेशान और 'बैकफुट' पर हैं तथा 'इंडिया' की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संसदीय दल की बैठक में विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' को देश का अब तक का सबसे 'दिशाहीन' गठबंधन करार दिया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे नामों का हवाला देते हुए कहा कि केवल देश के नाम के इस्तेमाल से लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दावा किया, अंग्रेजों के गुलाम तो भाजपा के राजनीतिक पूर्वज ही थे। प्रधानमंत्री जी, अपनी ऊल-जुलूल बयानबाजी से देश का ध्यान भटकाना बंद कीजिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा देश के युवाओं को रोजगार, जनता को महंगाई से राहत, हर तबके की खुशहाली, किसानों-श्रमिकों की भलाई, महिलाओं को सुरक्षा व सहायता, देश में एकता, प्रेम व शांति का सकारात्मक एजेंडा है। प्रियंका ने आरोप लगाया, आपने (प्रधानमंत्री) राजनीति के चलते 'इंडिया' के लिए नकारात्मक और अपमानजनक रुख अपना रखा है। बार-बार देश के नाम के साथ नकारात्मक मायने जोड़ना आपके पद की गरिमा के प्रति उचित नहीं है। देश के लोग नकारात्मक नहीं, सकारात्मक राजनीति चाहते हैं। संसद में मणिपुर पर देश आपकी बात सुनना चाहता है। देश महंगाई और बेरोज़गारी पर जवाब चाहता है।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री 26 दलों वाले गठबंधन 'इंडिया' से बहुत परेशान हैं। वह न केवल लगभग मृतप्राय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में नयी जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि आज सुबह अपने बयान के माध्यम से उन्होंने राजग को एक नया अर्थ 'नेशनल डिफेमेशन अलायंस' (राष्ट्रीय

मानहानि गठबंधन) दिया है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने ट्वीट कर कहा, मोदी जी, आप कांग्रेस विरोध में इतने अंधे हो गए कि इंडिया से ही नफरत करने लग गए। सुना है आज कुंठा में आकर आपने इंडिया पर ही हमला बोल दिया।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने दावा किया कि 'इंडिया' का नाम सुनकर मोदी जी और भाजपा पूरी तरह से परेशान हैं और 2014 के बाद शायद पहली बार ऐसा हो रहा है, जब प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा, मोदी जी संसद के बाहर ज्ञान मत दीजिए। संसद में आइए। हम लोग चार दिन से इंतजार कर रहे हैं कि आप संसद में आकर मणिपुर पर जवाब देंगे। हम जानते हैं कि पटना और बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक के बाद आप 'बैकफुट' पर हैं।

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने दावा किया कि जब से विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' बना है, तब से प्रधानमंत्री मोदी को पता चल गया है कि उनकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चतुर्वेदी ने कहा, दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री देश के नाम की तुलना एक आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं। यह सब बौखलाहट का असर है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद मनोज झा ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री के सलाहकार उनका बहुत ही नुकसान कर रहे हैं। महोदय को जल्द ही एक बेहतर शब्द कोश और बेहतर ऐतिहासिक समझ वाली पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं। जय हिंद। जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत।

खेल
प्रमुख समाचार

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का नौवीं टेस्ट सीरीज पर कब्जा

त्रिनिदाद। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-0 से जीत ली है। पोर्ट ऑफ स्पेन में दूसरा टेस्ट मैच मंगलवार को ड्रा हो गया और बारिश के कारण आखिरी दिन कोई खेल संभव नहीं हो सका। भारत जीत से आठ विकेट दूर था, जबकि वेस्टइंडीज को सीरीज बराबर करने के लिए पांचवें दिन 289 रनों की जरूरत थी। आयोजन स्थल पर भारी बारिश के कारण कुछ भी नहीं हुआ, जिससे दोनों कप्तानों को खेल जल्दी बंद करना पड़ा। यह वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की लगातार नौवीं टेस्ट सीरीज जीत है, जिसमें भारत ने टेस्ट की दूसरी पारी के दौरान सबसे तेज टीम 100 (12.2 ओवर) बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया।

मोहम्मद सिराज को पहली पारी में उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ 23.4-6-60-5 के आंकड़े के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बारिश ने उसकी क्लीन स्वीप करके विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के तीसरे चक्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण अंक जुटाने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। डब्ल्यूटीसी के पहले दो चक्र में फाइनल में पहुंचने वाले भारत ने डोमिनिका में खेला गया पहला टेस्ट मैच पारी और 141 रन से जीत कर नए चक्र की शानदार शुरुआत की थी। मैच के पांचवें और अंतिम दिन सुबह से ही मूसलाधार बारिश होती रही जिसके कारण खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में ही समय बिताना पड़ा। लंच के निर्धारित समय से कुछ देर पहले बारिश रुक गई और बादल भी छंट गए जिसके बाद अंपायरों ने भारतीय समयानुसार 11 बजकर 10 मिनट पर खेल शुरू करने की घोषणा की। अभी खिलाड़ी मैदान पर उतर पाते कि बादल घिर आए और बारिश होने लगी। अंपायरों ने इसके बाद दोनों कप्तानों की सहमति से भारतीय समयानुसार 12 बजकर 20 मिनट पर मैच ड्रॉ समाप्त करने की घोषणा की।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

उतार-चढ़ाव के बाद शेयर बाजार सपाट बंद

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों से मिले मिश्रित रुझानों और इंट्रा-डे ट्रेड में उतार-चढ़ाव के बाद सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार सपाट नोट पर बंद हुए। फ्रंटलाइन सूचकांक सेंसेक्स में मामूली गिरावट देखी गई। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी ने हल्की बढ़त दर्ज की। आज के कारोबार में सेंसेक्स लगभग 30 अंक कमजोर हुआ। वहीं, निफ्टी में 8 अंकों की दर्ज की गई। निवेशकों को अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर पर फैसले और कंपनियों के तिमाही नतीजों का इंतजार है। विदेशी कोषों की निकासी और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने भी निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 29.07 अंक यानी 0.04 फीसदी की मामूली गिरावट के साथ 66,355.71 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 66,559.29 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 66,177.62 तक आया।

लार्सन एंड टुब्रो को भारत, विदेश में 2,500 करोड़ रुपये तक के ठेके मिले

नईदिल्ली। लार्सन एंड टुब्रो ने मंगलवार को कहा कि उसे देश और विदेश में बिजली पारेषण और वितरण खंड में 1,000 करोड़ रुपये से 2,500 करोड़ रुपये तक के ठेके मिले हैं। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि उसे ये ठेके भारत और विदेश में मिले हैं। कंपनी ने कहा कि उसकी शाखा एलएंडटी कंस्ट्रक्शन को अपने बिजली पारेषण और वितरण व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण ठेके मिले हैं। घरेलू मोर्चे पर, ये ठेके गुजरात और झारखंड में मिले हैं। विदेश में ठेके सऊदी अरब और मलेशिया से संबंधित हैं। कंपनी ने इन ठेकों के मूल्य का खुलासा नहीं किया, लेकिन उसके परियोजना वर्गीकरण के अनुसार इनकी राशि 1,000 करोड़ रुपये से 2,500 करोड़ रुपये के बीच हैं।

रिलायंस ने ब्रुकफील्ड इंफ्रा-डिजिटल रियल्टी से किया करार

नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घोषणा की है कि वह भारत में डेटा सेंटर विकसित करने के उद्देश्य से स्थापित विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) में निवेश करने के लिए ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल रियल्टी के साथ एक समझौता कर रही है। कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि सौदे के तहत आरआईएल की प्रत्येक भारतीय एसपीवी में 33.33 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी और वह इनमें बराबर की भागीदार होगी। डिजिटल रियल्टी 27 देशों में 300 से अधिक डेटा केंद्रों के साथ विश्व स्तर पर क्लाउड और कैरियर न्यूट्रल डेटा सेंटर, कोलोकेशन और इंटरकनेक्शन समाधान से जुड़ी सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी का ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ संयुक्त उद्यम है। ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में उद्यमों और डिजिटल सेवा कंपनियों के लिए उच्च गुणवत्ता, अत्यधिक कनेक्टेड, स्केलेबल डेटा सेंटर विकसित करता है।

जम्मू-कश्मीर बैंक एनपीए में कमी के लिए ओटीएस योजना शुरू करेगा

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर बैंक अपनी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में कमी लाने के मकसद से कर्ज नहीं चुकाने वालों के लिए एक और एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) शुरू करेगा। बैंक के सीईओ और प्रबंध निदेशक बलदेव प्रकाश ने यह जानकारी दी। प्रकाश ने कहा कि जम्मू-कश्मीर बैंक पहले से ही ऋण वसूली के प्रति मानवीय नजरिया अपना रहा है। उन्होंने कहा, हम ऐसा कानून के दायरे में कर रहे हैं। हमने कर्ज नहीं चुकाने वालों के लिए पहले ही दो ओटीएस योजनाएं दी हैं और इनसे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा मिला। उन्होंने कहा, हम बहुत जल्द एक और ओटीएस शुरू करेंगे जो कम से कम तीन महीने तक लागू रहेगा। लोगों से मेरी अपील है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और अपना बकाया चुकाएं।

बैंकों के एनपीए पर हो ज्यादा ध्यान

जगदीश रत्नानी

बैंकिंग जगत में नॉन-परफॉर्मिंग ऐसेट्स या एनपीए के बारे में यह चर्चा सामान्य लग सकती है कि एनपीए बैंकिंग के कारोबार का एक हिस्सा है। कुछ कर्ज तो डूब ही जाएंगे, और कर्ज देने के कारोबार में यह हो ही सकता है। बात जायज लगती है, बस अंतर यह है कि जो बात सिद्धांत में सही लगती हो, जरूरी नहीं कि उसका पालन भी उसी भावना से होता है। कम-से-कम भारत के बैंकिंग जगत में तो यह नहीं हो रहा।

यह वह पेशा है, जिसमें छोटे कर्जदारों को पकड़ने में तो गजब की फुर्ती दिखाई जाती है, मगर बड़े कर्जदारों को छोड़ दिया जाता है। यह इस मशहूर कहावत को साकार करने के जैसा है - 'अगर आपको बैंक को 100 डॉलर चुकाना है, तो यह आपकी समस्या है। लेकिन, अगर आपको बैंक को 10 करोड़ डॉलर लौटाने हैं, तो यह बैंक की समस्या है।'

क्या यह तस्वीर हाल के समय में बदली है? पिछले कुछ हफ्तों से मीडिया में आयी रिपोर्टों से तो ऐसा ही लगता है, जिनमें बताया गया है कि एनपीए में नाटकीय रूप से कमी आयी है। इनमें 28 जून को रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि पिछले 10 साल में यह सबसे कम रह गया है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में कुल एनपीए 3.9% था, जो 2018 में 11.5% हुआ करता था।

लेकिन, इसी अवधि में कर्ज की राशि में भी वृद्धि हुई, जो वर्ष 2018 में 83.6 करोड़ रुपये से बढ़ कर 135 लाख करोड़ हो गयी है। ऐसे में, जब कर्ज का आकार बढ़ रहा है तो एनपीए में कमी को प्रतिशत के हिसाब से आंकने से शायद पूरी तस्वीर नहीं निकल सकती। फिर भी, सकल एनपीए में गिरावट

होना एक बदलाव है। आंकड़ों के आधार पर, आरबीए की रिपोर्ट में कहा गया है, 'एक ठोस बैंकिंग व्यवस्था की अगुआई में, भारत की वित्तीय व्यवस्था स्थिर बनी हुई है और अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं में सहायक है।' हालांकि, यह तस्वीर थोड़ी अलग लगेगी यदि एनपीए के मुद्दे को एनपीए के नये मामलों की संख्या के आधार पर समझा जाए। यदि पुराने एनपीए की संख्या इसलिए घट गयी क्योंकि बड़ी संख्या में कर्जों को माफ कर दिया गया, और उसके बाद नए एनपीए बनते रहे, तो ऐसे में अलग तरह के सवाल पैदा होते हैं। बैंकों के पास जितना भी पैसा है, वह भारत के आम नागरिकों का पैसा है। लोगों की बचत के पैसे से बैंक कारोबारियों को पूंजी उपलब्ध कराते हैं, और कारोबारियों को इस पैसे का निवेश करना चाहिए,

ताकि आर्थिक वृद्धि जारी रहे। तो फिर सकल एनपीए कैसे कम हो गया? कर्ज की सख्ती से उगाही अच्छा है, उसे माफ कर देना बुरा है। कर्ज अदायगी को लेकर सख्ती से तगादा करना, और जहां जरूरी हो वहां आपराधिक कार्रवाई करने से ऐसा लगेगा कि एनपीए के बढ़ते संकट पर लगाम लगाने के लिए गंभीरता दिखाई जा रही है।

बहुत मुमकिन है कि कर्ज में फंसे कारोबार वास्तव में मुश्किल में हों। लेकिन अक्सर होता यह है, कि या तो कर्ज की उगाही में ढिलाई बरती जाती है या फिर लोग जानकर कर्ज नहीं चुकाते। वर्ष 2021-22 में सकल एनपीए 5.8 फीसदी था जो राशि में 7.44 लाख करोड़ रुपये होती है। यह संख्या उस वर्ष की शुरुआत के 8.35 लाख करोड़ के एनपीए की राशि से कम है। कमी की सबसे बड़ी वजह कर्जों का माफ किया जाना था। माफ किये गये कर्ज की राशि 1.79 लाख करोड़ रुपये थी।

अहम बात यह है, कि 2021-22 में 2.83 लाख करोड़ रुपये के नये एनपीए शामिल हो गये। यह अभी तक का उपलब्ध नवीनतम आंकड़ा है। दरअसल, पिछले पांच वर्षों में (2018-2022), जब सकल एनपीए 9.2 फीसदी से घट कर 5.8 फीसदी रह गया, कुल 10.25 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया गया। इसी अवधि में, 20 लाख करोड़ से थोड़े कम, नये एनपीए जुड़ गये। इसी अवधि में, माफ कर दिये गये कर्जों, या चुका दिये गये कर्जों की तुलना में, नये एनपीए की संख्या ज्यादा हो गयी।

आखिर गठबंधन पर फिर से क्यों बढ़ा जोर

अनिल सिन्हा

बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों के सम्मेलन में इंडियन नैशनल डेमोक्रेटिक इनक्लूसिव अलायंस (इंडिया) नामक नए गठबंधन के ऐलान और नई दिल्ली में बीजेपी की ओर से एनडीए को फिर जिंदा किए जाने के प्रयास ने भारतीय राजनीति में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। राजनीतिक दलों में नए सिरे से ध्रुवीकरण हो रहा है। जाहिर है, लोग इन घटनाओं को 2024 के लोकसभा चुनावों से जोड़ कर देख रहे हैं। इसमें शक नहीं है कि आने वाले चुनावों पर इसका असर होगा। यह भी सही है कि चुनावी मजबूरियों ने ही ऐसे दलों को भी साथ ला दिया है, जो एक-दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। कुछ के आपसी संबंध तो इतने खराब थे कि उन्होंने साथ न आने की कसम खा रखी थी। फिर भी बारीकी से देखें तो दोनों ही घटनाएं देश को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाली हैं। इनका असर चुनावों पर होगा जरूर, लेकिन यह चुनावों तक ही सीमित नहीं रहेगा। अगर विपक्ष और सत्ता पक्षों के बीच होने वाली बयानबाजी को किनारे रख दें तो बेंगलुरु में हुए 26 राजनीतिक पार्टियों के सम्मेलन की सबसे खास बात यह रही कि इसने पिछले सालों में भारतीय राजनीति के लगातार व्यक्ति-केंद्रित होते जाने की प्रवृत्ति और दलों के एक-दूसरे से अलग चलने की रणनीति पर रोक लगा दी है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के दर्जनों दिग्गज नेताओं ने एक-दूसरे की मौजूदगी को न केवल माना है, बल्कि साथ चलना तय किया है। अभी हाल तक यही हाल था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ सीपीएम का कोई नेता बैठने को तैयार नहीं था। पटना सम्मेलन में दोनों दल शामिल थे, फिर भी यह भरोसा नहीं हो रहा था कि वे एक-दूसरे को बर्दाश्त करेंगे। हाल में हुए पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में ममता और कांग्रेस-वाम मोर्चा के गठबंधन के बीच जमकर संघर्ष हुआ और ममता ने बीजेपी के साथ कांग्रेस-वाम मोर्चा गठबंधन को बुरी तरह हराया। इसके बाद भी तीनों दलों के नेता न केवल साथ बैठे बल्कि एक गठबंधन का हिस्सा बन गए। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से हाथ मिला लेना भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। कांग्रेस की दिल्ली इकाई में इसका इतना विरोध था कि दिल्ली सरकार के प्रशासनिक अधिकारों को कम कर देने वाले केंद्र के अध्यादेश के विरोध का फैसला भी कांग्रेस नेतृत्व नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि इससे आम आदमी पार्टी को राजनीतिक फायदा हो जाएगा। लेकिन आखिर में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हो गई ताकि विपक्षी पार्टियों की एकता में कोई बाधा नहीं पैदा हो। ऐसे उदाहरण बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से भी दिए जा सकते हैं। इसमें कई पार्टियों के नेता सार्वजनिक रूप से कसम ले चुके थे कि कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ऐसी घटनाओं को आम तौर पर राजनीतिक अवसरवाद के रूप में पहचाना जाता रहा है। लेकिन मौजूदा हालात में दोनों तरफ चली इस एकीकरण प्रक्रिया को अवसरवाद बताकर खारिज करना ठीक नहीं होगा। खासकर यह देखते हुए कि इस प्रक्रिया में वामपंथी पार्टियों की भी सक्रिय हिस्सेदारी है। कम से कम वामपंथी पार्टियों के बारे में यह बात कुछ भरोसे के साथ कही जा सकती है कि वे राजनीति के लचीलेपन और कथित व्यवहारिकता से काफी हद तक दूर रही हैं। आइडियॉलजी के नाम पर इन दलों ने कई बार ऐसे फैसले लिए हैं, जो उनके लिए विनाशकारी साबित हुए।

विपक्षी सीटों का बँटवारा अग्नि परीक्षा

योगेंद्र योगी

बेंगलुरु मीटिंग में कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि पार्टी को पीएम पद की चाहत नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने खुद साफ किया कि पार्टी को पीएम पद नहीं चाहिए, बल्की वे संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिर्पेक्षता और सामाजिक न्याय के लिए लडऩा चाहते हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट करके जाहिर कर दिया कि एकता यदि नहीं हो पाती है तो उसकी तोहमत उसे नहीं लगनी चाहिए। इसके बाद अन्य दलों के लिए मानो दावेदारी के रास्ते खुल गए हैं। 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा? इसको लेकर विपक्षी खेमे में आवाज उठने लगी है। टीएमसी ने सबसे पहले दावेदारी ठोक दी है। टीएमसी सांसद सताब्दी रॉय ने मुख्यमंत्री ममता के लिए पीएम पद पर दावा ठोक दिया। कहा कि फिर %हम चाहेंगे की ममता बनर्जी (पीएम) बनें। मसलन, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल को उनकी पार्टी के नेता-कार्यकर्ता प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं। हालांकि, नीतीश कुमार इसी साल साफ कर चुके हैं कि उनका %प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं है।

ममता बनर्जी ने इस बारे में न तो इनकार किया है और ना ही स्वीकार, वहीं अरविंद केजरीवाल का सपना छिपा नहीं है। वह अपने लगभग भाषणों में इस बात की चर्चा करते हैं और मंत्रमुग्ध होते हैं कि %देश का पीएम पढ़ा-लिखा होना चाहिए। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदावार की जिस चुनौती को विपक्षी दल झेल रहे हैं, वह भाजपा के सामने नहीं हैं। भाजपा से हाथ मिलाने वाले 38 दलों को पता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ही इस पद के उम्मीदवार होंगे। हालांकि भाजपा के लिए भी क्षेत्रीय दलों के साथ सीट शेयरिंग मुश्किल भरा रास्ता होगा, किन्तु इतना नहीं जितनी मुश्किलों का सामना विपक्षी दलों को करना पड़ेगा। असली मुद्दा विपक्षी दलों के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर होना तय होगा। प्रधानमंत्री पद का मुद्दा हो सकता है उसके बाद तय हो। यह दोनों मुद्दे विपक्षी दलों के लिए लोहे के चने चबाने से कम नहीं हैं। कांग्रेस की चार राज्यों में खुद की और तीन राज्यों में गठबंन की सरकार है। कहीं डीएमके तो कहीं राजद-जेडीयू, जेएमएम के साथ गठबंधन में हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार, बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साफ सहित कई दूसरे दलों के नेता इस बात पर सहमत होते हुए राय व्यक्त कर चुके हैं कि कांग्रेस उनके राज्यों से दूर रहे। ये दल नहीं चाहते कि भाजपा के साथ-साथ उन्हें कांग्रेस से भी चुनावी मुकाबला करने पड़े। ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रीय दलों का सत्ता में हिस्सेदारी का सपना कमजोर पड़ता है।

कांग्रेस ने अभी तक इस मुद्दे पर पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस नहीं चाहती कि लोकसभा सीटों की शेयरिंग और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के मुद्दों को अभी से हवा देकर विपक्षी एकता में रुकावट पैदा करे। इससे विपक्षी दलों को कांग्रेस के खिलाफ बोलने का मौका मिल जाएगा और कांग्रेस इस एकता के टूटने का आरोप अपने सिर नहीं लेना चाहती। यह निश्चित है कि कांग्रेस को यदि देश और दिल्ली की राजनीति करनी है तो विपक्षी दलों के सीट शेयरिंग फार्मूले को नकारना होगा। फिलहाल कांग्रेस तेल और तेल की धार देखने के मूड में है। कांग्रेस अभी पूरी ताकत से विपक्षी दलों के साथ मिलकर केंद्र की भाजपा सरकार के प्रति हमलावर की मुद्रा में है और इस तेवर को पीएम सहित किसी तरह के मुद्दे को हवा देकर की कमजोर नहीं करना चाहती।

विपक्षी एकता में लोकसभा चुनाव की सीट शेयरिंग सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर किसी तरह की जल्दबाजी दिखा कर कांग्रेस अपने माथे पर एकता के टूटने का ठीकरा नहीं फुड़वाना चाहती। यही वजह है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री पद की दावेदारी और सीट शेयरिंग के मामले में खुलकर प्रतिक्रिया जाहिर करने से हिचकिचा रही है। दरअसल कांग्रेस को भी अंदाजा है कि प्रधानमंत्री पद की मजबूत दावेदारी उसी पार्टी की बनेगी जिसके पास ज्यादा सांसद होंगे। दूसरे दल सांसदों की संख्या के आधार पर ही मंत्री और दूसरे महत्वपूर्ण पदों की दावेदारी कर सकते हैं किन्तु पीएम पद के लिए सांसदों की सर्वाधिक संख्या होने आवश्यक है, अन्यथा इसी आधार पर दावा कमजोर पड़ जाएगा।

विपक्षी दलों की असली अग्नि परीक्षा सीटों की शेयरिंग को लेकर होनी हैं। विपक्षी दल पिछली दो बैठकों में इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट निर्णय करने से बचते रहें हैं। लेकिन इस मुद्दे पर रुख साफ किए गए एकता का मसला आगे नहीं बढ़ सकता। भाजपा द्वारा विगत चुनावों में हाशिए पर धकेले गए क्षेत्रीय दल फिर से खड़े होने की फिराक में हैं। ऐसे में उनका पूरा जोर इसी बात पर रहेगा कि उनके राज्यों से कांग्रेस मैदान से हट जाए। इससे कांग्रेस को मिलने वाले वोट भी उनकी झोली में आ सके। कांग्रेस यदि विपक्षी दलों के इस प्रस्ताव को मंजूर कर लेती है तो उसका जनाधार और संगठन, दोनों कमजोर पड़ जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस के लिए क्षेत्रीय दलों का यह प्रस्ताव गले की फांस बना हुआ है। हालांकि मुंबई में होने वाली विपक्षी दलों की तीसरी बैठक में ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि यदि ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है। कांग्रेस इस मुद्दे पर दोराहे पर खड़ी है। यदि विपक्षी दलों का सीट शेयरिंग प्रस्ताव स्वीकार करती है तो पहले से ही भाजपा द्वारा कमजोर कर देने के बाद और कमजोर हो जाएगी। यदि कांग्रेस प्रस्ताव का विरोध करती है कि विपक्षी एकता का होना संभव नहीं होगा। ऐसे में विपक्षी को एकता में अड़चन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने का मौका मिल जाएगा, कांगेस फिलहाल ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी।

विपक्षी दल एकता के इस गठजोड़ के लिए फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं। पटना में बैठक का आयोजन यह देखने और भाजपा को दिखाने के लिए किया गया कि खुले तौर पर कितने दल उनके साथ हैं। इसीलिए यह बैठक सिर्फ मेलजोल तक सीमित रही। यहां तक कि बैठक में विपक्षी गठजोड़ का नाम तक तय नहीं किया गया। बेंगलुरु में हुई बैठक में राजनीतिक दल विपक्षी एकता में एक कदम आगे बढ़ गए। बैठक में सर्वसम्मति से गठजोड़ का नाम भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (इंडिया) तय किया गया। इसके पीछे सोच यह भी रही कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अक्सर सभाओं में इंडिया का नाम लेते हैं, इसीलिए अब उनके लिए नाम लेना मुश्किल होगा। विपक्षी एकता की असली चुनौती मुंबई में होने वाली तीसरी बैठक में होगी। यह भी संभव है कि इस बैठक में भी सीट शेयरिंग, पीएम पद तथा चुनाव लड़ने के राष्ट्रीय मुद्दे तय नहीं किए जाए, बैठक में संचालन समिति तय हो सकती है। इस तरह की कवायद करने को कुश्ती में दंडबैठक से ज्यादा कुछ नहीं माना जा सकता। भाजपा से मुकाबले में आने के लिए विपक्षी को असली मुद्दों पर आना पड़ेगा। सीट शेयरिंग सहित अन्य मुद्दों से पता चल सकेगा कि विपक्षी एकता में कितना दमखम है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

दक्षिणामूर्त्युपनिषद् (भाग-3)

गतांक से आगे...

मन्त्र के द्वारा न्यास करें सर्वप्रथम तारं अर्थात् फिर परा बीज ह्रीं पुन: रमाबीज श्रीं कहे, इसके बाद साम्बशिवाय पुन: तुभ्यं और अन्त में स्वाहा का उच्चारण करे। इस प्रकार यह द्वादश अक्षर वाला मनु मंत्र है। (मन्त्र इस प्रकार बनता है ? ह्रीं श्रीं साम्बशिवाय तुभ्यं स्वाहा)। (ध्यान) जिन भगवान् शंकर ने अपने हाथों में वीणा, पुस्तक एवं अक्षमाला धारण कर रखी है, एक हाथ जिनका अभय मुद्रा में है तथा श्यामवर्ण के घनघोर बादल की तरह जिनका कण्ठ प्रदेश सुशोभित है, जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हैं, जिनके कटिभाग पर नागराज शोभित हैं, जो वट वृक्ष के नीचे विराजमान हैं तथा शुकादि मुनियों से सेवित हैं, उन भगवान् (शंकर) की मैं प्रार्थना करता हूँ।

इस मन्त्र के विष्णु ऋषि, अनुष्टुप् छन्द, दक्षिणा मुख (मूर्ति) देवता हैं, इससे न्यास करे। सर्वप्रथम तार अर्थात् पुन: नमो भगवते तुभ्यं फिर वटमूल पद उच्चारण करे, इसके बाद वासिने पद कहकर वागीशाय कहे, फिर महाज्ञान एवं दायिने मायिने पद को कहते हुए नम: शब्द का उच्चारण करे। (मन्त्र इस प्रकार हुआ-सभी श्रेष्ठ मन्त्रों में उत्तम यह आनुष्टुभमन्त्रराज है। ध्यान-जिनके हाथ अभय मुद्रा, पुस्तक एवं अग्नि तुल्य महाभयंकर सर्पों से सुशोभित हैं, प्रसन्न मुख वाले हैं, मोतियों के हार से सुशोभित हैं, चन्द्रमा की कला से मुकुट अधिक शोभा पा रहा है, जो अज्ञानान्धकार को समाप्त करने वाले हैं, जिन्हें वाणी से नहीं जाना जा सकता, जो आदि पुरुष हैं, सबके हैं, वटवृक्ष के नीचे निवास करने वाले भगवान् शिव का अभीष्टप्राप्ति के लिए हम ध्यान करते हैं। मौन मुद्रा वह परमात्मा मैं ही हूँ, इस भाव की पूर्ण स्थिरता मृत्युपर्यन्त बनी रहे, वही निष्ठा है। मनु मन्त्रों को परब्रह्म से अभिन्न मान कर बार-बार उच्चारण अर्थात् निरन्तर जप करना ही ज्ञान का साधन है। उस परमात्मा में एकाग्रचित्त होकर ध्यान लगाना ही उपकरण सामग्री है। शरीर के अंगों अर्थात् इन्द्रियों की चेष्टाओं को बार-बार रोकना एवं उन्हें भगवत्कार्य में नियोजित करना ही बलि है (स्व अविद्या पद, स्थूल तथा सूक्ष्म बीज के रूप में ये तीनों धाम ही काल हैं। (परमात्मा को प्राप्त करने का स्थान हृदय या सहस्रार है, इसलिए यह) द्वादशान्त पद ही स्थान है। उन श्रद्धावान् ऋषियों ने मार्कण्डेय ऋषि से पुन: प्रश्न किया किस प्रकार इसका उदय होता है? क्या स्वरूप है ? इसका उपासक कौन है? उन्होंने कहा वैराग्य रूपी तेल से परिपूर्ण, भक्ति रूपी वर्तिका से युक्त ज्ञानरूपी पात्र में ज्ञप्ति (ज्ञान का विषय) रूपी दीपिका अर्थात् सर्वत्र समान रूप से व्याप्त ईश सत्ता का अपनी आत्मा के रूप में दर्शन होता है।

क्रमश: ...

कारगिल विजय दिवस

अभिनय आकाश

26 जुलाई यह महज एक तारीख नहीं यह दिन है याद दिलाने के लिए कि देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए कुर्बानी क्या होती है। यह दिन है उन तमाम रणबांकुरे के आगे नमन करने का जो अपने आप को वर्दी में बांधकर देश को सुरक्षित फिजाओं में आगे बढ़ने का मौका देते हैं। यह दिन है उन तमाम साहसी जवानों के आगे झुककर नतमस्तक हो जाने का जो सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए अग्रसर होते हैं। वह है वतन, देश, हिंदुस्तान हमारा, इंडिया, हमारा भारत...

कारगिल युद्ध को 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं और सारा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। लेकिन यह जो विजय है यह आसानी से नहीं मिली थी हमारे 20, 22, 25 साल के जवानों ने इस विजय के लिए और अपने देश की धरती की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों की चोटियों पर लड़ा गया यह युद्ध दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध माना जाता है। देखा जाये तो कारगिल में युद्ध की नौबत इसलिए आयी क्योंकि 160 किलोमीटर के दायरे में हमारे निगरानी तंत्र की विफलता के चलते वहां पाकिस्तानी सेना घुस आई थी और हमारी कई चौकियों पर कब्जा जमा लिया था। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने मुख्यत: उन भारतीय चौकियों पर कब्जा जमाया था

जिनको भारतीय सेना की ओर से सर्दियों के मौसम में खाली कर दिया जाता था। लेकिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया और लगभग दो महीने तक चले इस युद्ध में विजय हासिल करते हुए पाकिस्तानी सेना को उलटे पांव भागने पर मजबूर कर दिया और पाकिस्तानी घुसपैठियों की ओर से कब्जाई गई अपनी चौकियों को छुड़ा लिया।

कारगिल की सबसे ऊँची चोटी टाइगर हिल से पाकिस्तान को खदेड़ कर वहाँ तिरंगा फहराते भारतीय सैनिकों की तसवीरें आपके जेहन में ताजा होंगी लेकिन ऊपर बैठकर गोली बरसा रहे पाकिस्तानी सैनिकों से इस क्षेत्र को छुड़ाना कोई आसान काम नहीं था। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना और वायुसेना ने अपनी जबरदस्त जांबाजी दिखाई लेकिन इस दौरान हमारे लगभग 500 जवानों ने अपनी शहादत भी दी। भारतीय जवानों के लिए सबसे मुश्किल बात यह थी कि वह नीचे थे और दुश्मन ऊँचाई पर बैठ कर हमें साफ-साफ देख भी रहा था और गोलियां बरसा कर नुकसान पहुँचा रहा था। कल्पना करके देखिये कि ऐसे में क्या माहौल होगा जब दुश्मन के गोले और गोलियों से बचते हुए हमारे जवानों के सामने ऊपर चढ़ने की कठिन चुनौती भी है, रसद और गोला बारूद भी साथ लेकर जाना है, दुश्मन को ठिकाने भी लगाना है और उस समय सेना के पास आज की तरह रात में देख सकने वाले अत्याधुनिक उपकरण और कई अन्य प्रकार के साजो-सामान नहीं थे। कारगिल की ऊँची पहाड़ियों पर जहाँ सांस लेना भी मुश्किल होता है वहां हिम्मत दिखाते हुए बस आगे बढ़ते जाना है। कारगिल की लड़ाई आखिर क्यों हुई? यह सवाल आने वाली पीढ़ी जरूर पूछेगी। तो आइए आपको जरा युद्ध से पहले के हालात से अवगत कराते हैं। पाकिस्तानी सेना के मन से यह टीस कभी नहीं गयी कि उसे हर बार भारत के साथ युद्ध में हार झेलनी पड़ी। वह सीधे मुकाबले से बचते हुए धोखे से भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं। पाकिस्तान कहने को तो लोकतांत्रिक देश है लेकिन वहां मालिक सेना ही है और इसी पाकिस्तानी सेना ने भारत से एक और युद्ध की तैयारी अंदर ही अंदर 1998 में ही शुरू कर दी थी।

संसदीय लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे

ललित गर्ग

मानसून सत्र में दोनों सदनों में सुचारू रूप से चलें इसके लिये सर्वदलीय बैठक में सहमति भले ही बनी हो, लेकिन अब तक के अनुभव के अनुसार यह सत्र भी हंगामेदार ही होना तय है। भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए विपक्ष ने 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस (इंडिया)' नाम के नए गठबंधन की घोषणा कर दी है। नए गठबंधन के नेता संसद के मानसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी कर चुके हैं। मानो विपक्षी दलों ने प्रण कर लिया है कि वह इस सत्र को भी सुगम तरीके से नहीं चलने देगा। मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ और यह 11 अगस्त को खत्म होगा। इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें रखी गई हैं। एक ओर जहां सत्ता पक्ष अहम विधेयकों को पारित करने की कोशिश में है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष मणिपुर हिंसा, रेल सुरक्षा, महंगाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड और अडाणी मामले पर जेपीसी गठित करने की मांग करने में लगा हुआ है। कई और मुद्दों को लेकर भी वह सरकार को घेरने की फिराक में है। ऐसे में, विपक्ष की भूमिका देश व सरकार के प्रति अपने कर्तव्य और दायित्व के सही एवं सकारात्मक निर्वहन की होनी अपेक्षित है।

हम पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि किस प्रकार संसद के सत्र छोटे पर छोटे होते जा रहे हैं और साल में संसद बामुश्किल 55 या 56 दिन के लिए ही बैठती है और उसमें भी सार्थक चर्चा होने के स्थान पर सत्ता व विपक्षी खेमों के बीच एक-दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोपों की बौछार होती रहती है और भारी शोर-शराबा मचता रहता है या बैठकें बार-बार स्थगित होती रहती हैं। विपक्ष का आक्रामक रुख और हंगामा उचित नहीं है। उसे अपनी छवि सुधारनी चाहिए। हर बार की तरह इस बार भी संसदीय अवरोध कायम रहता है तो इससे लोकतंत्र कमजोर ही होगा। लोकतंत्र में संसदीय अवरोध जैसे उपाय किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इस

मौलिक सत्य व सिद्धांत की जानकारी से आज का पक्ष एवं विपक्षी नेतृत्व अगर अनभिज्ञ रहता है, तो यह अब तक की हमारी लोकतांत्रिक यात्रा की कमी को ही दर्शाता है। यह स्थिति देश के लिये नुकसानदायी है, इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की काली छाया से मानसून सत्र को बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए।

भारत पूरी दुनिया में संसदीय प्रणाली का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है और इसके बावजूद इसकी संसद की हालत ऐसी हो गई है कि सदन चलता ही नहीं। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने में अब केवल मुश्किल से नौ महीने ही बचे हैं। इस अवधि में विपक्ष प्रभावी भूमिका में सामने आये, यह जरूरी है। वैसे भी संसद पर पहला अधिकार विपक्ष का होता है क्योंकि वह अल्पमत में होता है मगर उसी जनता का प्रतिनिधित्व करता है जिसका प्रतिनिधित्व बहुमत का सत्ताधारी दल करता है। अत: विपक्ष द्वारा उठाये गये मुद्दों और विषयों पर विशद चर्चा कराना सत्ताधारी दल का नैतिक कर्त्तव्य बन जाता है। मगर हम तो देखते आ रहे हैं कि पिछले सत्र में जिस प्रकार एक के बाद एक विधेयक बिना चर्चा के ही संसद के दोनों सदनों के भीतर भारी शोर-शराबे के बीच पारित होते रहे, यहां तक कि चालू वित्त वर्ष के बजट को भी बिना किसी चर्चा के ही ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धुंधलाने के उपक्रम है। मानसून सत्र के दौरान सरकारी कार्यों की संभावित सूची में 31 नये विधेयकों को पेश या पारित करने के लिए शामिल किया गया है। इसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 को भी जोड़ा गया है। यह विधेयक संबंधित अध्यादेश का स्थान लेने के लिए रखा जाएगा। आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना लगा रही है। हम भयंकर गलती कर रहे हैं क्योंकि हम उसी संसद को अप्रासंगिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसके साये में इस देश का पूरी शासन-व्यवस्था चलती है और जिसमें बैठे हुए आम जनता के प्रतिनिधि आम लोगों से ताकत लेकर उसे चलाने की जिम्मेदारी उठाते हैं और इस मुल्क के हर तबके के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए नीतियां बनाते हैं। भारतीय संविधान के तहत संसद को सार्वभौम इस तरह माना गया है कि इसे नये कानून बनाने का भी अधिकार है, बशर्ते वे कानून संविधान की कसौटी एवं जन-अपेक्षाओं पर खरे उतरते हों। इन कानूनों को पारित करने में सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष की भूमिका है, मगर हमने पिछले सत्र में देखा कि विपक्षी सांसदों ने संसद का बहिष्कार करके या उसका अवरोध करके उसको नहीं चलने दिया और पूरा सत्र व्यर्थ ही चला गया।

मानसूत्र सत्र व्यर्थ न जाये, यह पक्ष एवं विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। इस सत्र में अहम विधेयक पेश किए जाने हैं, ऐसे में सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। सभी दलों को सत्र चलाने में मदद करनी होगी। संसदीय कार्यमन्त्री का मुख्य कार्य विपक्ष के साथ संवाद कायम करके संसदीय कामकाज को सामान्य तरीके से चलाने का होता है। मगर इसके साथ ही दोनों सदनों के सभापतियों की भी यह जिम्मेदारी होती है कि वे संसद की कार्यवाही को चलाने के लिए संसदीय कार्यमन्त्रणा समितियों से लेकर विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं से सहयोग एवं सहृदयता प्राप्त करने का प्रयास करें। लेकिन जैसे-जैसे लोकतंत्र के विस्तार के साथ देश की भौतिक अवस्था में भी सकारात्मक बदलाव आया है, उससे तो कल्पना में यही बात रही होगी कि बौद्धिकता का भी स्तर और अभिव्यक्ति की शैली में प्रगतिशीलता और श्रेष्ठता आएगी। लेकिन यथार्थ इससे एकदम भिन्न है। बहस की शैली और तत्त्व दोनों में ही गिरावट आई है। संसदीय बहसें अपने सुनने-देखने वालों की भी रचनात्मकता को कम करने में अधिक कारगर हो रही हैं। यही कारण है कि हल्की, ऊटपटांग, उलाहनापूर्ण, व्यंग्य और अपशब्दों वाली बहसें एवं हंगामे, जिन्हें संक्षेप में अमर्यादित और असंसदीय कह सकते हैं, जो लोकतंत्र की गरिमा को धूमिल करती है, इन स्थितियों का उभरना एक चिन्तनीय स्थिति है।

संसद में हम अगर सार्थक बहस या रचनात्मक चर्चा को ही टालने का प्रयास करेंगे तो आम जनता में जनप्रतिनिधियों के बारे में जो सन्देश जायेगा वह संसद की गरिमा के हक में नहीं होगा क्योंकि हर पांच साल बाद तो हर पार्टी का प्रत्याशी जनता से बड़े-बड़े वादे करके ही वोट यह कह कर पाता है कि वह लोकसभा में पहुंच कर आम जनता का दुख-दर्द व उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा करेगा और राष्ट्र की नीतियों के निर्माण में अपना योगदान देगा। लेकिन हर सांसद को यह योगदान देने के लिये तत्पर होना चाहिए एवं उनके दलों को भी यह भूमिका निभानी चाहिए। संसदीय अवरोध कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, उससे हम प्रतिपल देश की अमूल्य धन-सम्पदा एवं समय-सम्पदा को खोते हैं, जिनकी भरपाई मुश्किल है। इसके साथ ही राजनीतिक मूल्य, भाईचारा, सद्भाव, लोकतंत्र के प्रति निष्ठा, विश्वास, करुणा यानि कि जीवन मूल्य भी खो रहे हैं।

विपक्ष हंगामे पर उतारू न होकर सार्थक चर्चा करे, उसके विरोध के स्वरों में देशहित होना चाहिए जबकि अभी स्वहित है। पक्ष एवं विपक्ष दोनों को ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लोकतन्त्र में संसद के सत्र कोई समारोह नहीं हैं बल्कि यह हमारी देश-निर्माण की प्रशासनिक व्यवस्था की अन्तरंग प्रणाली हैं। संसद केवल वाद-विवाद का प्रतियोगिता स्थल नहीं होती बल्कि लोकहित व राष्ट्रहित में फैसला करने का सबसे ऊंचा मंच होती है। एक प्रश्न है कि यदि केवल बिना बहस कराये ही भारी शोर-शराबे के बीच ध्वनिमत से ही विधेयक पारित कराने हैं तो संसद की क्या प्रासंगिकता रहेगी?

बापू की दिनचर्या

मौन

बापू बाईस वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की सेवा करने के अनंतर सन् 1915 में भारत लौटे। यहाँ आने पर जनमानस के अध्ययन की दृष्टि से अपने राजनीतिक गुरु गोखलेजी के आदेशानुसार वे एक वर्ष तक देशभर में मौनपूर्वक भ्रमण करते रहे। इस अवधि में उन्होंने लोगों से विचार-विमर्श किया और लेख लिखे, किसी कार्य का श्रीगणेश नहीं किया। बाद में सन् 16 से उन्होंने स्वराज्य एवं जन-जागरण का कार्य आरंभ किया। उनको भाषण, लेखन तथा पत्राचार करना पड़ा। स्थान-स्थान पर विभिन्न भाषाओं में भाषण, चर्चा तथा भेंट-वार्ता करते-करते उनकी वाणी और कंठ दोनों में इतनी थकावट आ गई कि उन्हें इन दोनों को विश्राम देने की आवश्यकता का अनुभव हुआ और सन् 1921 से उन्होंने प्रत्येक सोमवार को चौबीस घंटे का मौनव्रत आरंभ किया। कुछ काल के अभ्यास के पश्चात् उन्होंने इसके मानसिक तथा आध्यात्मिक महत्त्व का अनुभव किया। सहसा उन्हें ऐसा आभास हुआ कि परमात्मा से संपर्क बनाए रखने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग मौन ही है। बाद में उन्होंने इसे अपने स्वभाव का अंग महसूस किया। मौन-व्रत आरंभ करते समय बापू ने अपने लिए एक अपवाद रखा और वह यह कि स्वयं को असह्य शारीरिक पीड़ा होने या किसी अन्य की शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा निवारण करने की स्थिति उत्पन्न होने पर वह भंग हो सकता। वाइसराय तथा देश के प्रमुख नेताओं से मौनवार को ही अत्यावश्यक वार्ता की स्थिति आने पर वे या तो मौन-व्रत शीघ्र आरंभ करते, जिससे सोमवार को प्रात:काल आवश्यक वार्त्ता निबटाकर कुछ देर बाद मौनारंभ करते और चौबीस घंटे व्यतीत करके मंगलवार को मौन त्याग करते। सोमवार को अत्यावश्यक वार्त्ता का कार्यक्रम होने पर वे कभी-कभी एक दिन पूर्व-रविवार को मौन रहते। सामान्यत: हर रविवार की शाम को वे मौन शुरू करते जो सोमवार की शाम तक चलता। महादेव भाई की गंभीर बीमारी के समय बापू ने अपना मौन भंग कर दिया था। मगनलाल भाई के देहावसान के पश्चात् बापू ने सर्वप्रथम मौन तोड़ा था। इसी प्रकार 7 जून, 42 को रविवार था। अगले दिन पं. जवाहरलाल नेहरू को उनसे बातें करनी थीं, अत: उन्होंने रविवार को मौन रखा। काका साहब कालेलकर के शब्दों में सिद्धांत-निष्ठा के साथ व्यवहार को सँभालने की बापू की खूबी सचमुच अद्भुत थी। कई लोग व्यवहार की अनिवार्यता की दुहाई देकर सिद्धांत को छोड़ देते हैं।

क्रमश: ...

अजीत डोभाल ने की चीनी राजनयिक के साथ बैठक

वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर बनी स्थिति पर हुई चर्चा

■ गलवान के बाद भारत-चीन के रिश्तों को नुकसान हुआ है

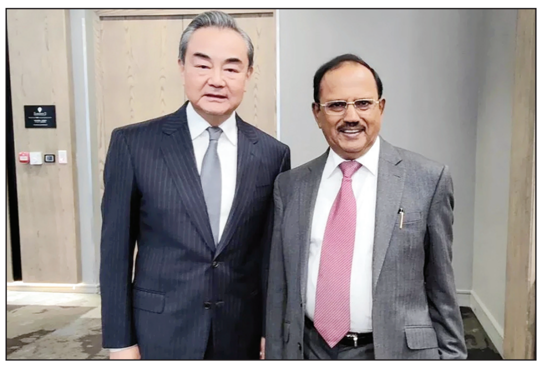

नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने सोमवार, 24 जुलाई को रिष्ठ चीनी राजनयिक वांग यी के साथ बैठक की। सीमा पर जारी तनाव के बीच चीनी राजनयिक के साथ एनएसए डोभाल की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में अजीत डोभाल ने चीनी राजनयिक वांग यी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 2020 के बाद भारत-चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर जो स्थिति बनी है उससे भारत-चीन के रिश्तों को नुकसान हुआ है। डोभाल ने चीनी राजनयिक से कहा कि एलएसी पर जारी हालात ने रणनीतिक विश्वास और रिश्ते के सार्वजनिक और राजनीतिक आधार को खत्म कर दिया है।

बैठक के दौरान, एनएसए ने स्थिति को सुलझाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए निरंतर प्रयासों के महत्व पर भी जोर दिया ताकि द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। डोभाल और वांग यी की ये मुलाकात दक्षिण अफ्रीका में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक के इतर हुई। यह बैठक विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा इंडोनेशियाई राजधानी जकार्ता में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के विदेश मामलों के आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग से मुलाकात के कुछ दिनों बाद हुई।

बैठक के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि भारत-चीन द्विपक्षीय संबंध न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि क्षेत्र और दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

बता दें कि गलवान में 2020 में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद से ही एलएसी पर कई क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों से गतिरोध बना हुआ है। दोनों पक्षों ने कई राजनयिक और सैन्य वार्ताओं के बाद कई क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी पूरी कर ली है। लेकिन अब भी हालात सामान्य नहीं है।

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, डोभाल के साथ बैठक के दौरान वांग यी ने कहा कि दोनों पक्षों को रणनीतिक आपसी विश्वास बढ़ाना चाहिए, आम सहमति और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बाधाओं को दूर करना चाहिए और द्विपक्षीय संबंधों को जल्द से जल्द मजबूत और स्थिर विकास की पटरी पर लाना चाहिए। वांग ने कहा कि चीन न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सहित विकासशील देशों के साथ काम करने के लिए तैयार है।

चीन के लापता विदेश मंत्री को पद से हटाया गया

बीजिंग। वांग यी को चीन का नया विदेश मंत्री बनाया गया है। चीन की सरकारी मीडिया ने मंगलवार को यह जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार लापता विदेश मंत्री

किन गैंग को हटा दिया गया और वांग यी ने उनकी जगह ले ली है। दरअसल, किन गैंग कहां है, यह अभी तक अज्ञात है। गैंग आखिरी बार सार्वजनिक कार्यक्रम के तहत 25 जून को दौरे पर आए रूसी, श्रीलंकाई और वियतनामी अधिकारियों के साथ बैठक में नजर आए थे। इसके बाद से उन्हें नहीं देखा गया है। उनके मंत्रालय ने बाद में कहा था कि वह स्वास्थ्य कारणों से काम से दूर हैं।

चीन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका समेत 11 देशों के 30 हजार से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। भारत समेत चार देश इस युद्धाभ्यास के ऑब्जर्वर हैं। बता दें कि इस युद्धाभ्यास को चीन की चुनौती से निपटने के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि चीन लगातार हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है, यही वजह है कि इस युद्धाभ्यास को बेहद अहम माना जा रहा है।

ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न स्थानों पर हो रहे इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ ही फिजी, फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी के सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। वहीं भारत, सिंगापुर, फिलीपींस और थाइलैंड इस युद्धाभ्यास के ऑब्जर्वर हैं। खास बात ये है कि अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया विवादित ताइवान स्ट्रेट में भी युद्धाभ्यास करेंगे। यहीं पर चीन ने बीते दिनों युद्धाभ्यास किया था। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के ताइवान स्ट्रेट में युद्धाभ्यास से चीन नाराज हो सकता है।

उल्लेखनीय है कि हिंद प्रशांत महासागर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। दुनिया का 80 प्रतिशत व्यापार इसी क्षेत्र से होता है। ऐसे में अगर इस क्षेत्र में अस्थिरता या सुरक्षा को लेकर कोई

दिक्कत होती है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। यूक्रेन युद्ध की वजह से यह पहले ही बाधित चल रही है।

ऑस्ट्रेलिया में हो रहे युद्धाभ्यास को तलिसमन सेब्रे नाम दिया गया है। यह युद्धाभ्यास हर दो साल में होता है और साल 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी। इस साल यह युद्धाभ्यास इसलिए खास है क्योंकि इस बार का युद्धाभ्यास सबसे बड़ा है।

चीन ने ऑस्ट्रेलिया में हो रहे युद्धाभ्यास पर निशाना साधा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एक लेख में इस युद्धाभ्यास को कागज के शेर बताया। चीनी विशेषज्ञों का आरोप है कि अमेरिका सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के नाम पर देशों पर दबाव बना रहा है और इसकी आड़ में अपने वैश्विक आधिपत्य को बनाए रखना चाहता है।

ज्ञानवापी मामले से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर सुनवाई पूरी, 28 अगस्त को होगा फैसला

नई दिल्ली। ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मंदिर भूमि स्वामित्व विवाद से संबंधित कई याचिकाओं में पक्षों से कुछ स्पष्टीकरण मांगने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज मामले में सुनवाई पूरी की और मामलों पर फैसला सुनाने की तारीख 28 अगस्त तय की। न्यायालय के समक्ष दायर याचिकाओं में वाराणसी अदालत के समक्ष दायर एक मुकदमे की स्थिरता को चुनौती भी शामिल है, जिसमें उस स्थान पर एक मंदिर की बहाली की मांग की गई है जहां ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है।

पीठ के समक्ष एक और याचिका अंजुमन मस्जिद समिति ने वाराणसी कोर्ट के 2021 के आदेश को चुनौती दी है। मस्जिद परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि 17 वीं शताब्दी में ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण के लिए एक हिंदू मंदिर को आंशिक रूप से तोड़ा गया था या नहीं। गौरतलब है कि वाराणसी न्यायालय के समक्ष लंबित मामले की कार्यवाही पर सितंबर 2021 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी, साथ ही एएसआई सर्वेक्षण आदेश पर भी प्रभावी रूप से रोक लगा दी थी।

वाराणसी कोर्ट का आदेश स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से वकील विजय शंकर रस्तोगी द्वारा दायर याचिका पर आया था। आवेदन वर्ष 1991 में प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर और 5 अन्य द्वारा दायर एक मुकदमे में दायर किया गया था, जिसमें उस भूमि की बहाली का दावा किया गया था जिस पर ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं के लिए है। मुकदमे में वादी ने यह घोषित करने की मांग की कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वह हिंदुओं की है। जैसा कि सर्वविदित है, भूमि स्वामित्व विवाद कथित तौर पर काशी विश्वनाथ मंदिर के खंडहरों पर बनी ज्ञानपवी मस्जिद से संबंधित है। मुकदमे को एचसी के समक्ष चुनौती दी गई है और उक्त चुनौती को विवाद से संबंधित कई मामलों के साथ जोड़ दिया गया है। पिछले साल, न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ ने मामलों में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, हालांकि, अदालत ने इस साल मई में कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे और इसलिए, मामलों को नियमित अंतराल पर सूचीबद्ध किया गया था। अब सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी है।

गहलोत सरकार में बैठे लोगों के कारण राज्य में अपराध बढ़ रहा है : गुढ़ा

अगले कुछ दिनों में रैली करने और जनता के बीच जाने की घोषणा की

जयपुर। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री और कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुढ़ा अब अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ खुल कर मैदान में आ गए हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा जहां एक तरफ अगले कुछ दिनों में रैली करने और जनता के बीच जाने की घोषणा की है वहीं आरोप लगाया है कि गहलोत सरकार में बैठे लोगों के कारण राज्य में अपराध बढ़ रहा है।

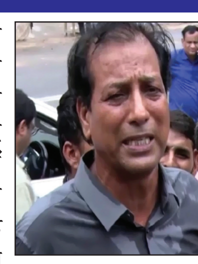

राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा, अगले 5-7 दिनों में हम एक बड़ी रैली करेंगे, जिसमें लगभग 50,000 लोग आएंगे, रैली के बाद हम तय करेंगे कि क्या करना है। मैं लोगों के बीच जाऊंगा और महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाऊंगा। पूरे मंत्रिपरिषद का नार्को टेस्ट होना चाहिए। आरोपी सरकार में बैठे हैं और उनकी वजह से राजस्थान महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और अत्याचार में नंबर 1 बन गया है। मुझे विधानसभा में बोलने के अधिकार, राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और अन्य अत्याचार का विरोध करने पर बर्खास्त किया गया। गुढ़ा यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, दुष्कर्म में शतक बना चुके लोग मंत्री बने बैठे हैं। सबसे बड़े दुष्कर्मी तो मंत्रिपरिषद के अंदर हैं। अगर, मेरी बात गलत साबित हो जाए तो मैं राजनीत ही छोड़ दूंगा। बता दें कि गहलोत सरकार में सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा में अपनी ही सरकार को महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा किया था। गुढ़ा ने कहा था कि हमें मणिपुर की चिंता छोड़कर अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सीएम अशोक गहलोत ने एक पत्र लिखकर राज्यपाल कलराज मिश्र से गुढ़ा को बर्खास्त करने की अनुशंसा कर दी। फिर राजेंद्र गुढ़ा मंत्री से पूर्व मंत्री हो गए। विधानसभा में राजेंद्र गुढ़ा एक लाल डायरी लेकर आए थे जिसके बारे में उनका दावा है कि उसमें विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ी जानकारी थी। गुढ़ा जब अध्यक्ष की कुर्सी के करीब पहुंचे तो कांग्रेस विधायकों के साथ धक्का मुक्की हुई। हंगामे के बाद मार्शलों ने गुढ़ा को राजस्थान विधानसभा से बाहर कर दिया था। राजस्थान के झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी विधानसभा सीट से विधायक राजेंद्र गुढ़ा का कहना है कि इस लाल डायरी में विधायकों की खरीद फरोख्त का हिसाब था और सीएम अशोक गहलोत ने ही उनसे ये डायरी लाने को कहा था और इसे जलाने का आदेश दिया था।

29 तक भारत की यात्रा पर रहेंगे अमेरिका के विशेष दूत केरी

नई दिल्ली। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि जलवायु के लिए अमेरिका के विशेष दूत जॉन केरी 25 से 29 जुलाई तक नई दिल्ली और चेन्नई का दौरा करेंगे। यह यात्रा 19 जुलाई को केरी की चीन यात्रा के बाद हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप कोई नया समझौता नहीं हुआ। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक भाषण में कहा था कि चीन अपनी गति से कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण को चरणबद्ध तरीके से खत्म करेगा।

अपनी चीन यात्रा पर बोलते हुए केरी ने कहा कि हमारे बीच बहुत स्पष्ट बातचीत हुई लेकिन हम यहां नई जमीन हासिल करने आए हैं। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि हमें थोड़ा और काम करने की जरूरत है। दिल्ली में केरी वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से मिलेंगे और चेन्नई में वह जी20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्रियों (ईसीएसएम) की बैठक में भाग लेंगे।

अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि जलवायु के लिए विशेष राष्ट्रपति दूत जॉन केरी जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा पर साझा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए 25-29 जुलाई को नई दिल्ली और चेन्नई, भारत की यात्रा करेंगे, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण समाधानों में निवेश के लिए एक मंच बनाने, शून्य-उत्सर्जन बसों की तैनाती का समर्थन करने और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के पारस्परिक प्रयास शामिल हैं। पिछली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह (ईसीएसडब्ल्यूजी) की बैठक, जो 21 मई को हुई थी, वह भी भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत थी।

लोकसभा में जैव-विविधता पर बिल पास

ओम बिरला बोले- नारे लगाना समाधान नहीं

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। मणिपुर में हिंसा पर विपक्षी दलों के विरोध के बीच लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार शाम पांच बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच लोकसभा में आज जैव विविधता संशोधन बिल पर चर्चा हुई और सदन ने जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह विधेयक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण और पारिस्थितिक असंतुलन के तिहरे संकट का सामना कर रही है। जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक 16 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव द्वारा संसद में पेश किया गया था।

यह विधेयक जैविक विविधता अधिनियम, 2002 में संशोधन करेगा। इस को 20 दिसंबर, 2021 को एक संयुक्त समिति में स्थानांतरित कर दिया गया था, क्योंकि बिल में चिंता जाहिर की गई थी इसके कुछ प्रावधान उद्योगों के पक्ष में है।

संयुक्त समिति ने 2 अगस्त, 2022 को संसद में अपनी रिपोर्ट इस सिफारिश के साथ प्रस्तुत की कि उनकी सिफारिशों को शामिल करने के बाद विधेयक को पारित किया जा सकता है। कई सांसदों ने विधेयक में संशोधन के फायदों पर बात की और कहा कि इसके लाभ में जैव-विविधता को कंपनी अधिनियम के साथ जोड़ना भी शामिल है।

मणिपुर में हिंसा को लेकर विपक्षी दल लगातार संसद में हंगामा कर रहे हैं और पीएम मोदी मणिपुर मुद्दे पर बोलने और केंद्र सरकार संसद में चर्चा के लिए बोल रहे हैं। वहीं मंगलवार को भी जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य मणिपुर का मुद्दा उठाते हुए नारे लगाने लगे। अध्यक्ष ओम बिरला ने विरोध कर रहे सदस्यों से नारेबाजी नहीं करने को कहा और उनसे अपनी सीटों पर वापस जाने का अनुरोध किया।

ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि नारे लगाने से मुद्दों का कोई समाधान नहीं होगा, वे प्रश्नकाल की अनुमति दें क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। विरोध जारी रहने पर कार्यवाही को स्थगित कर दिया।

संसद में विपक्ष के नेता का माइक किया गया बंद : डेरेक ओ ब्रायन

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने मंगलवार को आरोप लगाया कि संसद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) गठबंधन का प्रत्येक सदस्य विरोध में संसद से बाहर चला गया। विपक्षी दल संसद के मौजूदा मानसून सत्र के दौरान मणिपुर मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दोपहर में जब सदन की बैठक शुरू हुई तो प्रश्नकाल की शुरुआत से ही हंगामा शुरू हो गया, कांग्रेस और अन्य समान विचारधारा वाले दलों के सदस्यों ने मणिपुर, मणिपुर के नारे लगाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी आरोप लगाया कि भाजपा सांसदों ने खड़गे को बोलने से रोका। उन्होंने आगे कहा कि सदन के नेता के अलावा किसी और के उकसावे पर बार-बार बाधा डालने और शोर-शराबे में विधेयकों को पारित करने की जिद के कारण इंडिया ब्लॉक से संबंधित सभी सांसदों ने बहिर्गमन किया। शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के दौरान रोका और आखिरकार उनका माइक बंद कर दिया गया। खड़गे ने सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया था और कहा था कि 50 से अधिक सदस्यों ने नियम 267 के तहत मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है, लेकिन सरकार तैयार नहीं है। खड़गे ने कहा, जब इतने सारे लोग इस बारे में बात करना चाहते हैं तो वे बात करने को तैयार क्यों नहीं हैं? मोदी साहब यहां आकर स्थिति क्यों नहीं समझाते? बाहर तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, लेकिन सदन में वो मणिपुर के बारे में बात करने को तैयार नहीं हैं।

पाक ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती प्रांत पर किया हमला, तालिबान ने की जवाबी कार्रवाई

इस्लामाबाद। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) द्वारा आतंकवादी हमलों को लेकर इस्लामाबाद और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर द्वारा काबुल को धमकी दिए जाने के कुछ दिनों बाद पाकिस्तानी बलों ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत पर गोलाबारी की। रिपोर्टों में कहा गया है कि पाकिस्तानी बलों ने अफगान सीमा पर कथित टीटीपी ठिकानों पर गोलाबारी की जिसके बाद तालिबान बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। अफगानिस्तान में टीटीपी की मौजूदगी को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव के बीच यह झड़प हुई। कथित झड़प पर काबुल या इस्लामाबाद की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

पाकिस्तान ने इस सप्ताह अपने विशेष दूत को तीन दिवसीय यात्रा पर काबुल भेजा ताकि यह स्पष्ट संदेश दिया जा सके कि अंतरिम सरकार को टीटीपी के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी होगी। लेकिन अफ़ग़ान तालिबान ने कई बैठकों के बाद उनसे कहा कि पाकिस्तान को बल प्रयोग के बजाय शांति का रास्ता अपनाना चाहिए। राजदूत आसिफ दुर्रानी ने अपनी यात्रा के दौरान अफगानिस्तान के कार्यवाहक उप प्रधान मंत्री मावलवी अब्दुल कबीर, कार्यवाहक विदेश मंत्री मावलवी अमीर खान मुत्ताकी और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की।

बंद दरवाजे की बातचीत से परिचित आधिकारिक सूत्रों ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि अफगान तालिबान नेतृत्व को स्पष्ट शब्दों में बताया गया था कि टीटीपी के मुकाबले पाकिस्तान का धैर्य कमजोर हो रहा है। विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज ज़हरा बलूच ने अपनी साप्ताहिक समाचार ब्रीफिंग में बताया कि आतंकवाद का मुद्दा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, पिछली ब्रीफिंग में भी पाकिस्तान के लिए गंभीर चिंता का मुद्दा है।

लोकसभा चुनावों तक हर महीने यूपी में भाजपा जोड़ेगी विपक्षी नेताओं को

लखनऊ। बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बड़ी रणनीतियां बन रही हैं। इनमें एक सबसे अहम रणनीति का हिस्सा विपक्षी दलों के नेताओं को अपने साथ शामिल करने का भी बना है। केंद्र से लेकर राज्य के प्रमुख पार्टी नेताओं ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी अपनी तय योजना के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले तक प्रदेश की सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, उनको अपने साथ जोड़ने का महाअभियान चलाने जा रही है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने विशेष बातचीत में बताया कि जल्द और अलग अलग पार्टियों से जुड़े नेता उनके साथ आने वाले हैं।

भाजपा ने 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। इन्हीं तैयारियों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सभी छोटे और बड़े सियासी दलों में सेंध लगानी शुरू कर दी है। इन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। यही नहीं पार्टी अपनी नई रणनीति के मुताबिक जल्द ही और भी कई बड़े नेताओं को अपने साथ शामिल कर दूसरे दलों को कमजोर करते हुए 2024 की मजबूत टीम बना रही है। पार्टी ने इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी और उत्तर प्रदेश की अन्य स्थानीय पार्टियों के नेताओं समेत सुभासपा जैसी पार्टी को अपने साथ जोड़ लिया है। जबकि सोमवार को बसपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य राजपाल सैनी, सपा सरकार में मंत्री रहे साहब सिंह सैनी व जगदीश सोनकर, पूर्व विधायक सुषमा पटेल, अंशुल वर्मा सहित सपा, बसपा, रालोद व कांग्रेस के नेताओं को अपने साथ कर लिया है।

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी कहते हैं कि अभी तो हमारे साथ कुछ लोग ही आए हैं। उनका कहना है कि आप देखते जाइए धीरे-

धीरे बहुत से लोग हमारी पार्टी में जुड़ते जाएंगे। इसके पीछे तर्क देते हुए वह कहते हैं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर देश और प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं वह सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी कहते हैं कि वह उन सभी लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं जिनकी विचारधारा उनकी पार्टी से मिल रही है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का होना ही महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख दलों के बड़े नेता उनके संपर्क में हैं। वह कहते हैं कि जल्द ही उन सभी एक विचारधारा वाले नेताओं को अपने दल में शामिल करा के देश और प्रदेश में पार्टी के नेटवर्क को मजबूत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि उनके साथ जो लोग भी आ रहे हैं वह राजनीति के एक बड़े मुकाम पर पहुंचे हुए राजनेता है। इसलिए उनके अनुभवों से पार्टी भी मजबूत होगी और जनाधार भी बढ़ेगा।

भारतीय जनता पार्टी अपने इस अभियान में हर तरीके के सियासी समीकरणों को भी जोड़कर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। जिस तरह से भाजपा ने सोमवार को पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक विपक्षी दलों को झटका दिया, भाजपा के नेताओं की नजर में वह महज एक शुरुआत भर है। पश्चिमी यूपी में सैनी समाज का बड़ा वोट बैंक है। इस समाज के वोट पर साहब सिंह सैनी और राजपाल सिंह सैनी का खासा प्रभाव है। राजपाल ने 2022 में खतौली से रालोद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। पूर्वांचल में जौनपुर के मुंगराबादशाहपुर सीट से सपा विधायक रहीं सुषमा पटेल कुर्मी समाज से हैं। पार्टी पूर्वांचल में कुर्मी समाज में अपना जनाधार बढ़ाना चाहती हैं। पूर्व विधायक जगदीश सोनकर चार बार विधायक रहे हैं। पूर्वांचल के सोनकर समाज में उनकी मजबूत पकड़ है। इसी तरह पार्टी में आगरा से बसपा के नेता रवि भारद्वाज और बसपा से खेरागढ़ से चुनाव लड़ने वाले गंगाधर कुशवाहा को भी लखनऊ में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं का मानना है कि इस मिशन दोस्ती अभियान के तहत उन सभी लोगों को जोड़ा जाना जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को मजबूत कर सके। इस अभियान के तहत हर महीने उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी पार्टी से जुड़े प्रभावशाली नेताओं को जोड़ा जाना है। इसके लिए पार्टी के भीतर उन सभी दूसरे दलों के प्रमुख नेताओं की सूची भी बनाई जा चुकी है जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं।

जानें, कैसे हुई महातारा की उत्पत्ति और क्यों कहा जाता है उन्हें नीला तारा

हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह में आने वाले शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को महातारा जयंती के पर्व मनाया जाता है। मां महातारा दस महाविद्या में से शक्ति का उग्र व आक्रामक रूप हैं। देवी तारा को सूर्य प्रलय की अधिष्ठात्री देवी का उग्र रूप कहा गया है। देवी तारा को तारिणी विद्या के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन तंत्र-मंत्र से पूजा करके देवी को खुश किया जाता है। देवी तारा शक्ति स्वरूपा हैं। जब उनका कोई भक्त चारों तरफ निराशा से घिर जाता है, तब मां उनकी मदद करने के लिए अवश्य आती हैं।

कैसे हुई देवी महातारा की उत्पत्ति- पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले जब चारों और अंधकार फैला हुआ था। उस समय अंधकार की देवी मां काली थी तब घोर अंधकार से एक प्रकाश की किरण उत्पन्न हुई, जिन्हें तारा कहा गया। मां तारा अक्षोभ्य नाम के ऋषि पुरुष की शक्ति हैं, ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, सभी की स्वामिनी देवी तारा ही मानी जाती हैं। देवी की उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति के समय हुई इसलिए उन्हें महातारा भी कहा जाता है। सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी तारा मोक्ष की प्राप्ति के लिए सहायक मानी जाती हैं।

क्यों कहा जाता है उन्हें महानीला व नीला तारा- एक किवदंती के अनुसार समुद्र मंथन के समय बहुत सारी चीजें बाहर निकली। जब विष बाहर आया तो देवताओं ने भगवान शिव के सामने मदद की गुहार की। तब भोलेनाथ ने विश्व कल्याण के लिए सारा विष पी लिया। उन्होंने इस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया। मां भगवती ने अपने आराध्य की पीड़ा महसूस कर ली और विष के प्रभाव को कम करने के लिए मां भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर गई। इस वजह से देवी का रंग नीला हो गया और इस वजह से उनका नाम महानीला व नीलतारा पड़ा।

[भविष्यफल]

मेष
आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आप काफी सक्रिय रहेंगे। कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी। दिन आनंद पूर्वक बीतेगा। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। यात्रा का अवसर मिलेगा। जीवनसाथी से पूर्ण सहयोग मिलेगा। शुभ चिंतकों की सलाह पर ध्यान देना चाहिए।

वृष
आज आपका दिन मंगलमय होगा। सगे संबंधियों से मुलाकात हो सकती है। दिन उत्सव और आनंद में बीतेगा। शत्रुओं पर विजय कर पाएंगे। अधूरे कार्य संपन्न होंगे। कोई शुभ सूचना मन को प्रसन्न रखेगी। वैवाहिक जीवन में काफी रोमांटिक नजर आएंगे। बच्चों से खुशी मिलेगी।

मिथुन
आज आपका दिन बढिया रहेगा। लेखक और कलाकार अपने क्षेत्र में कुछ अलग और बेहतर कर सकते हैं। मन में कल्पना की तरंगे उठेंगी। रोमांटिक मूड में रहेंगे। लोगों से विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। आपका सम्मान और महत्व बढ़ेगा।

कर्क
आज आपका दिन मिलाजुला रहेगा। आपकी मन:स्थिति नकारात्मकता की ओर प्रेरित करेगी इसका ध्यान रखें। मन को सकारात्मक रखें। परिवार में आपसी तालमेल और सहयोग के लिए योगदान दें। खुद को सबल रखें। जीवनसाथी की भावनाओं को समझें धन लाभ होगा।

सिंह
आज आपका दिन उत्साह से भरपूर रहेगा। नींद अच्छी आएगी। मानसिक रूप से आज आप बहुत हल्कापन महसूस करेंगे। आपके मन पर छाए हुए चिंता के बादल हटने से आपके उत्साह में वृद्धि होगी। शॉपिंग कर सकते हैं, अपनों से मेल-मुलाकात होगी। यात्रा का योग है।

कन्या
आज आपका दिन मनोनुकूल रहेगा। आज रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। धन निवेश के लिए दिन लाभकारी है। स्वयं पर विश्वास रखकर ही आज कार्यों को क्रियान्वित करें। खान-पान के मामले में संयम रखें। सामाजिक जीवन में सक्रिय रह सकते हैं। यात्रा हो सकती है।

तुला
आज आपका दिन खुशनुमा व अनुकूल रहेगा। बीमार लोगों की सेहत में सुधार होगा। सुबह से ही आप सक्रिय रहेंगे और काम को समय पर पूरा कर लेंगे। पारिवारिक जीवन में प्रेम और आपसी सहयोग बढ़ेगा। दोपहर के बाद अधिक आनंदित और उत्साहित रहेंगे। यात्रा हो सकती है।

वृश्चिक
आज आपका दिन मिलाजुला रहेगा। सुस्ती रहेगी, खान-पान का ध्यान रखें। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप से बचें क्योंकि आज किसी का भला करने के चक्कर में आप खुद परेशानी में आ सकते हैं। पैसों की लेन-देन से दूर रहें। धर्म में नीयती रहेगी। स्वास्थ्य आज नरम रह सकता है।

धनु
आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। दिन विशेष लाभदायी है। निवेश, व्यापार, नौकरी, शिक्षा सभी क्षेत्रों में आज लाभ के संकेत हैं। सभी कार्य समय से पूरे होंगे। धर्म-कर्म में रुचि रहेगी। मान-प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। मित्रों और शुभचिंतकों से संवाद होगा, कोई अच्छी खबर मिलेगी।

मकर
आज आपका दिन ऊर्जावान रहेगा। आप आज हर काम सरलता से संपन्न कर पाएंगे। नौकरी में आपके उच्च अधिकारी खुश रहेंगे। कार्य की व्यस्तता रहेगी एवं स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन भी आज आनंद में बीतेगा। कोई उपहार भी मिल सकता है।

कुंभ
आज आपका दिन सही रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। पूर्वनिर्धारित कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। धार्मिक एवं मांगलिक कार्यो में व्यस्त रहेंगे। परिवार संग खान-पान का आयोजन हो सकता है। मित्रों और सहकर्मियों के सहयोग से मिलेगा।

मीन
आज आपका दिन बढिया रहेगा। आज का दिन संयम और शांति से गुजारें। किसी नए काम को शुरू करने के लिए दिन उचित नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं। दूसरों के मामलों से दूर रहना बेहतर होगा। कार्यक्षेत्र में स्थिति सामान्य रहेगी।

वामन द्वादशी की कथा

आज 2 अप्रैल, 2023 भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन द्वादशी का त्यौहार मनाया गया। आज के दिन भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के पुत्र के रूप में अवतार लिया था। वामन देव त्रेता युग के पहले अवतार थे। दक्षिण भारत में वामन भगवान को उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं मनुष्य के रूप में भगवान विष्णु का ये पहला अवतार था। विष्णु जी ने वामन अवतार में एक बौने ब्राह्मण का रूप लिया था। वामन देव को इंद्र देव का छोटा भाई भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं, क्या है भगवान वामन से जुड़ी कथा-

वामन द्वादशी कथा- पौराणिक कथाओं के अनुसार अत्यंत बलशाली दैत्य राजा बलि ने इंद्रदेव से देवलोक छीन लिया था। तब इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुंचे क्योंकि उन्हें डर था कि राजा महाबली परम शासक बन सकते हैं। भगवान विष्णु ने सबको विश्वास दिलाया कि वो जल्द ही इस समस्या का समाधान ढूढेंगे और उनको देवलोक वापस दिलवाएंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने वामन के रूप में धरती पर पांचवां अवतार लिया।

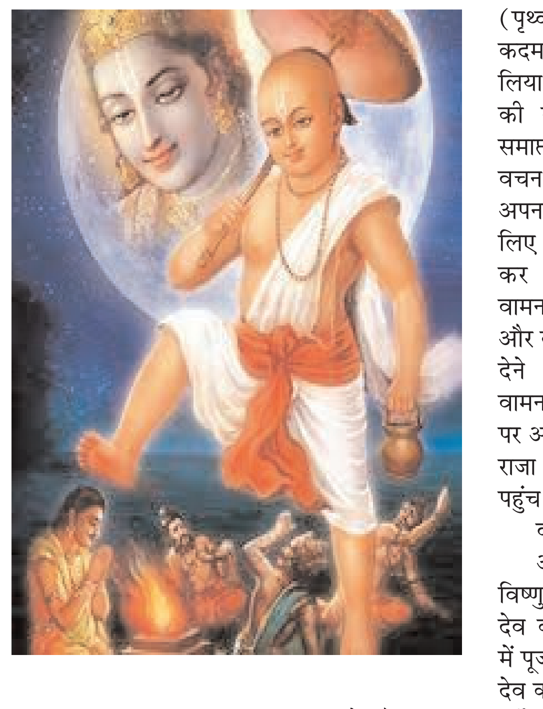

असुर राज बलि प्रह्लाद के पौत्र भी हैं इसलिए वो दयालु असुर के नाम से भी जाने जाते हैं। वामन देव बौने ब्राह्मण के वेश में बली के पास गये और उससे रहने के लिए तीन कदम भूमि मांगी। राजा बलि के द्वार पर जो कोई भी जाता था वो उसे कभी खाली नहीं भेजते थे। बलि ने गुरु शुक्राचार्य की चेतावनी के बावजूद वामन देव को वचन दे डाला।

वामन देव ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि पहले ही कदम में पूरा भूलोक (पृथ्वी) नाप लिया। दूसरे कदम में सारा देव लोक ले लिया। जब तीसरे कदम की बारी आई तो भूमि समाप्त हो गई थी लेकिन वचन के पक्के राजा बलि ने अपना वादा पूरा करने के लिए अपना सिर प्रस्तुत कर दिया। ये देखकर वामन देव बहुत खुश हुए और बलि को पाताल लोक देने का निश्चय किया। वामन देव ने बलि के सिर पर अपना पैर रखा, जिससे राजा बलि पाताल लोक में पहुंच गए।

वामन द्वादशी की पूजा

आज के दिन भगवान विष्णु के अवतार वामन देव का चित्र लगाकर घर में पूजा की जाती है। वामन देव की पूजा करने के लिए दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध लेकर उनका अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के बाद उनकी कथा सुनें और आरती के साथ पूजा का समापन कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव आपके और परिवार के ऊपर बना रहता है।

भीष्म पितामह ने पांडवों को दिया था ये उपदेश

महाभारत का धर्मयुद्ध अपने अंतिम चरण में था। भीष्म पितामह बाण शय्या पर लेटे जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। धर्मराज युधिष्ठिर जानते थे कि पितामह उच्चकोटि के ज्ञान और जीवन संबंधी अनुभव से सम्पन्न हैं। वह अपने भाइयों और पत्नी सहित उनके समक्ष पहुंचे और उनसे विनती की कि पितामह, ''आप विदाई की बेला में हमें ऐसी शिक्षा दें जो सदैव हमारा मार्गदर्शन करे।''

तब भीष्म ने बड़ा ही उपयोगी जीवन दर्शन समझाते हुए नदी और समुद्र के संवाद की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि नदी जब समुद्र तक पहुंचती है तो अपने जल के प्रवाह के साथ बड़े-बड़े वृक्षों को भी बहाकर ले जाती है। एक दिन समुद्र ने नदी से प्रश्न किया, ''तुम्हारा जल प्रवाह इतना शक्तिशाली है कि उसमें बड़े-बड़े वृक्ष भी बहकर आ जाते हैं पर कभी कोमल घास नहीं आती। ऐसा क्यों?''

नदी का उत्तर था जब-जब मेरे जल का बहाव तेज और प्रलयंकारी होता है, तब घास झुक जाती है और मुझे मार्ग दे देती है, किन्तु वृक्ष अपनी कठोरता के कारण ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए मेरा प्रवाह उन्हें बहा ले आता है। इस छोटे से उदाहरण से हमें सीखना चाहिए कि जीवन में हमेशा विनम्र रहें तभी व्यक्ति का अस्तित्व बना रहता है। सभी पांडवों ने भीष्म के इस उपदेश को ध्यान से सुनकर अपने आचरण में उतारा और सुखी हो गए।

मन में बनी रहती है घबराहट तो जरूर रखें यह पावन व्रत

सोमवार को प्रदोष तिथि आने पर इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत संतान प्राप्ति की कामना के लिए रखा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से दोष, रोग, शत्रु दूर हो जाते हैं। सुख-संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि मन में घबराहट बनी रहती हो और चित्त शांत ना रहता हो तो प्रति माह इस कल्याणकारी व्रत को जरूर करना चाहिये।

सोम प्रदोष व्रत करने वाले साधक पर भगवान शिव की कृपा बरसती है। सच्चे मन से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि एक प्रदोष व्रत करने का फल दो गायों का दान करने के बराबर मिलता है। प्रदोष व्रत में बिना कुछ खाए उपवास रखने का विधान है। यह संभव न हो तो एक बार फल खाकर उपवास कर सकते हैं।

सोम प्रदोष व्रत करने वाले साधक पर भगवान शिव की कृपा बरसती है। सच्चे मन से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि एक प्रदोष व्रत करने का फल दो गायों का दान करने के बराबर मिलता है। प्रदोष व्रत में बिना कुछ खाए उपवास रखने का विधान है। यह संभव न हो तो एक बार फल खाकर उपवास कर सकते हैं। सोम प्रदोष व्रत रखने से चंद्र ग्रह के दोष दूर होते हैं। सोम प्रदोष व्रत में व्रतधारी को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी को पंचामृत व गंगाजल से स्नान करा बिल्व पत्र, गंध, चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची अर्पित करें। भगवान शिव को घी और शकर मिले मिष्ठान्न या मिठाई का भोग लगाएं। आठ दीपक आठ दिशाओं में जलाएं। रात्रि जागरण करें। भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें। पूरे दिन मन ही मन ऊं नमः शिवाय का जाप करें। सोम प्रदोष व्रत में भगवान शिव का अभिषेक रुद्राभिषेक और उनका श्रृंगार करने का बहुत महत्व है।

जब इंद्र देव ने लगाई बादलों की क्लास

भगवान इन्द्र ने मौसम विभाग की बैठक बुलाई। बैठक में बादलों को भी बुलाया गया। मौसम विभाग के कर्मचारियों से उनके कार्यों की प्रगति रिपोर्ट मांगी। सबके कार्यों की समीक्षा हुई। बादलों की प्रगति रिपोर्ट से वह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बादलों को फटकार लगाई, ''कहां भटकते रहते हो। लोग बरसात के लिए तरस रहे हैं और तुम सैर-सपाटा करते फिरते हो।''

उन्होंने बादलों को निर्देश दिए, ''सावन नजदीक आ रहा है। पृथ्वी पर आपको जल अर्पित करना है। सभी अपनी-अपनी तैयारी कर लें। आपको सभी जगह पर समान रूप से बरसात करनी है। किसी भी बादल का यह बहाना नहीं चलेगा कि मेरी टंकी टूट गई थी, मेरी टंकी लीक हो गई थी या पानी रास्ते में ही बिखर गया था।''

''कुछ बादल हरियाली को देखकर लालच में आ जाते हैं। चेरापूंजी जैसी बारिश वे मुंबई में ही बरसा कर लौट आते हैं। इससे रेगिस्तान तो सूखा ही रह जाता है और अफरा-तफरी मच जाती है। राजस्थान से प्रार्थनाएं आ रही हैं। लोग पुकार रहे हैं। बरसात के लिए यज्ञ कर रहे हैं। हवन कर रहे हैं, मीठे चावल बांट रहे हैं।''

''बरसात होती नहीं होगी तो फसल कहां से होगी। ऊपर से तुम्हारे लिए इतना खर्च और खर्च के हिसाब से आप लोग इतना कार्य नहीं करते। अब यह सब नहीं चलेगा। समझ गए न सब लोग। इस बार रेगिस्तान में बरसात होनी चाहिए। इस बार नहीं बरसे तो ठीक नहीं रहेगा।''

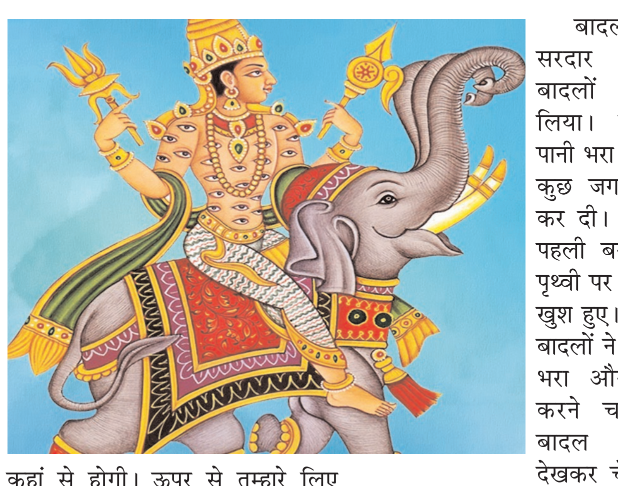

बादलों के सरदार ने सभी बादलों को साथ लिया। समुद्र से पानी भरा। धरती पर कुछ जगह बरसात कर दी। सावन की पहली बरसात थी। पृथ्वी पर सभी बहुत खुश हुए। दूसरे दिन बादलों ने फिर पानी भरा और बरसात करने चले। कुछ बादल हरियाली देखकर चेरापूंजी में रम गए। कुछ बादल मुंबई पर बरसात करके चले गए। आधा सावन यूं ही निकल गया। कुछ बादल आलसी थे। पानी भरते और आस-पास ही बरस जाते। इससे उन इलाके में बाढ़ की स्थिति बन गई। दूर-दराज का मैदानी इलाका सूखा रह गया। भगवान इंद्र को खबर मिली कि बादल जान-बूझकर ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने बादलों को डांट लगाई तो बादलों के सरदार ने कहा ''क्या करें महाराज, पानी ज्यादा भरा होता है। मैं उड़ रहा था कि पहाड़ों से टकरा गया। टक्कर से सारा पानी वहीं बिखर गया।''एक बादल बोला ''महाराज! मुंबई महानगर रास्ते में पड़ता है। वहां इतनी ऊंची-ऊंची इमारते हैं कि उड़ने का रास्ता ही नहीं मिलता। हम उन्हीं से टकरा जाते हैं। सारा पानी उस महानगर पर गिर जाता है।''

भगवान इंद्र ने कहा, ''मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। पृथ्वी पर सभी जगह बरसात होनी चाहिए। जल अर्पित करना हमारा कर्तव्य है। राजस्थान के लोग प्रार्थना कर रहे हैं। उन्हें जल्दी से जल्दी पानी पहुंचाओ। बादलो ने फिर पानी भरा और राजस्थान की तरफ चल पड़े। राजस्थान में सूखा रेगिस्तान देख कर बादलों के सरदार ने कहा, ''यहां बरसात करके क्या करोगे। यहां तो हरियाली ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं।''

पीछे-पीछे पानी से भरी एक नन्ही बदली आ रही थी। उसने देखा कि पास खड़ा मोर आंखों में आंसू लिए उसे निहार रहा था। सूखा-सा पौधा रेत में चांदी की तरह चमकते हुए अपनी रूखी जटाएं आसमान को दिखा रहा था। बिल्कुल शांत रेगिस्तान अपनी बांहें फैलाए उस नन्ही बदली को प्यार से बुला रहा था। यह देख कर वह भाव-विभोर हो गई और उन पर जमकर बरस गई।

फिर बोली, ''रुको, मैं और पानी लेकर आती हूं। नन्ही बदली गई और फिर से पानी लेकर आई। साथ में अपनी और सहेलियों को भी ले आई। उन सबने मिलकर रेगिस्तान में खूब बरसात की। नन्ही बदली व उसकी नन्ही सहेलियों ने देखा कि मोर पंख फैलाकर नाच रहा था और पौधों के पत्ते जैसे बहुत लम्बे समय बाद नहाए हों। नहाया हुआ रेगिस्तान नन्ही बदली को प्यार से निहार रहा था और आशीर्वाद दे रहा था। नन्ही बदली और उसकी सहेलियां यह दृश्य देख मंत्रमुग्ध हो गईं। उन्हें रेगिस्तान धरती पर सबसे खूबसूरत लग रहा था।

संक्षिप्त समाचार

उप मुख्यमंत्री सिंहदेव बेमेतरा और कवर्धा में विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा बेमेतरा और कवर्धा जिले के प्रभारी मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव बेमेतरा और कवर्धा में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। वे दोनों जिलों में संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों की भी समीक्षा करेंगे। श्री सिंहदेव 26 जुलाई को बेमेतरा में और 27 जुलाई को कवर्धा में बैठक लेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री सिंहदेव 26 जुलाई को रायपुर से सवेरे दस बजे सड़क मार्ग से बेमेतरा के लिए रवाना होंगे। वे सवेरे साढ़े 11 बजे बेमेतरा पहुंचकर जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। श्री सिंहदेव दोपहर तीन बजे बेमेतरा से कबीरधाम जिले के रणबीरपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। वे दोपहर साढ़े तीन बजे रणबीरपुर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे शाम साढ़े पांच बजे वहां से कवर्धा के लिए रवाना होंगे। श्री सिंहदेव शाम छह बजे कवर्धा पहुंचेंगे। वे कवर्धा में रात्रि विश्राम करेंगे। सिंहदेव अगले दिन 27 जुलाई को सवेरे 11 बजे कवर्धा में लोगों से मुलाकात करेंगे। वे दोपहर एक बजे अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। श्री सिंहदेव शाम साढ़े चार बजे कवर्धा से रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। वे शाम सात बजे रायपुर पहुंचेंगे।

मणिपुर हिंसा: आप ने किया प्रदर्शन राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग

रायपुर। मणिपुर की घटना को लेकर छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को रायपुर में नलघर चौक के पास विरोध प्रदर्शन किया। इसमें केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसमें शामिल होने के लिए प्रदेशभर से आप पदाधिकारी-कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रायपुर पहुंचे। मणिपुर में हुई अमानवीय घटना का विरोध किया। आप प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई। वहीं राष्ट्रपति से मणिपुर की भाजपा सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग की गई। दूसरी ओर मणिपुर मामले में आप के संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि रूश्सस्त्रद्ब जी के पास फ्रांस, यूएसए समेत पूरी दुनिया घूमने का समय है, लेकिन मणिपुर में हो रही हिंसा पर कोई एक्शन लेने का समय नहीं है। मोदी अगर मजबूत नेता हैं तो इस तरह से छुप क्यों रहे हैं? सदन में आकर बयान दे दें, वरना पूरे विपक्ष का विरोध चलते रहेगा।

आंगनबाड़ी केन्द्र की तीन सहायिकाये किए गए बर्खास्त

कोरिया। परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना बैकुण्ठपुर ने परियोजना अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र मानापारा की सहायिका श्रीमति शारदा, खलपारा की श्रीमति प्रमिला एवं बडगांव की सहायिका नालो बाई के द्वारा संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्रों में लगातार अनुपस्थिति, कार्य में अनियमितता, मद्यपान कर केन्द्रों का संचालन करना ऐसी शिकायत मिलने पर विभाग द्वारा जांच की गई, जांच उपरांत शिकायत सही सिद्ध हुई। परियोजना अधिकारी द्वारा संबंधित सहायिकाओं को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु संतोषप्रद जवाब नहीं होने पर अनुशानात्मक कार्यवाही करते हुए सहायिकाओं को पद से बर्खास्त कर दिया गया है।

14 जनपद पंचायत सीईओ के तबादले, आदेश जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत तबादला किया है जिसमें 14 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को नए स्थानों पर पदस्थ किया गया है। इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के मुताबिक हिमांशु गुप्ता जनपद पंचायत तखतपुर जिला बिलासपुर से अकलतरा जांजगीर चांपा,बीआर वर्मा बिल्हा बिलासपुर से कुरूद धमतरी, सत्यव्रत तिवारी अकलतरा जांजगीर चांपा से तखतपुर बिलासपुर, कुमार सिंह मस्तूरी बिलासपुर से आरंग रायपुर, किरण कुमार कौशिक आरंग से धमधा दुर्ग,आरएस नायक डभरा जांजगीर चांपा से सहसपुर लोहारा कबीरधाम, प्रदीप प्रधान पिथौरा महासमुंद से पथरिया मुंगेली ,क्रांति ध्रुव साजा बेमेतरा से सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा, राजेंद्र कुमार पडौती गुरुर जिला बालोद से मगरलोड जिला धमतरी, रोशनी भगत खैरागढ़ से अभनपुर रायपुर, प्रकाश मेश्राम धमधा दुर्ग से गुरुर बालोद,पन्नालाल ध्रुवे कवर्धा से साजा बेमेतरा,संदीप शाह पोयाम मालखरोदा जांजगीर चांपा से पिथौरा महासमुंद और प्रज्ञा यादव को पामगढ़ जांजगीर-चांपा से बरमकेला रायगढ़ पदस्थ किया गया है।

एयरपोर्ट से दुर्ग तक शुरु हुआ सिटी बस सेवा, देना होगा 100 रुपये किराया

रायपुर। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट माना से दुर्ग तक जाने वाली पूरी तरह वातानुकूलित (एयर कंडीशनर) सिटी बस का आज शुभारंभ किया गया है। आज सुबह 10.15 बजे स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन परिसर से इस बस को रवाना किया गया। शासन की पहल से अब दुर्ग से रायपुर तथा एयरपोर्ट माना तक आने-जाने के लिए लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो गई है। यह बस नवा रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से तेलीबंधा, पचपेड़ी नाका, भाठागाँव, टाटीबंध, पावर हाउस, नेहरू नगर होते हुए दुर्ग शहर तक चलेगी। बस स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन परिसर से सुबह 8.30, 10.15, दोपहर 2.30 और शाम 6.30 बजे छूटेगी।

किसानों की खुशहाली का माध्यम बनेगी पीएम प्रणाम योजना

■ 27 को प्रधानमंत्री राजस्थान के सीकर से करेंगे शुरुआत

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के सीकर में 27 जुलाई को एक विशाल जन सभा को संबोधित करते हुए पीएम किसान सम्मान निधि की 20 हजार करोड़ की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर करने के साथ ही पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में 40 लाख से अधिक पंजीकृत किसान हैं। इनमें से लगभाग 21 लाख किसानों को ही सम्मान निधि का लाभ मिल पा रहा है। कांग्रेस शासन की लापरवाही के कारण 20 लाख से अधिक किसान यहां सम्मान निधि से वंचित हैं। यह किसानों का अपमान है। कांग्रेस सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह केवायसी आदि की कार्यवाही पूर्ण कर आँकड़े दिल्ली भेजे लेकिन जान-बूझ कर इस काम में भूपेश सरकार लापरवाही कर रही है ताकि प्रदेश के किसानों को मोदी की योजना का लाभ नहीं पहुँचे। न केवल सम्मान निधि में बल्कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में भी ऐसा ही दुराग्रह का परिचय दे रही है। अभी तक फसल बीम की अधिसूचना भी जारी नहीं की है। उक्त बातें पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने पत्रकारवार्ता में कहीं।

उन्होंने कहा कि जिस तरह पीएम आवास योजना में 16 लाख परिवारों का आवास बनना रोक दिया है, जिनमें अधिकांश किसान ही हैं, वैसे ही फसल बीमा और किसान सम्मान निधि आदि मामले में किसानों को अपनी सस्ती और हल्की राजनीति का शिकार बना रही है। 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और ऐतिहासिक योजना पीएम प्रणाम की शुरुआत करने वाले हैं। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने की प्रधानमंत्री की कोशिश है इससे खेती में अन्य उर्वरकों के इस्तेमाल से खेती की गुणवत्ता बेहतर होगी। साथ ही किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि इससे खेती की लागत कम हो सकती है। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिये सरकार पीएम प्रणाम यानी कृषि प्रबंधन हेतु वैकल्पिक पोषक तत्वों का संवर्द्धन योजना शुरू करने की योजना बना रही है। पत्रकारवार्ता में भाजपा मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी व रायपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष टंकराम वर्मा उपस्थित थे।

इस योजना का उद्देश्य

जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के संयोजन के साथ उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना है। रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी के बोझ को कम करना, जो 2022-23 में 2.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुँचने का अनुमान है - 2021 के 1.62 लाख करोड़ रुपए के आँकड़े से 39 प्रतिशत अधिक है। उर्वरक सब्सिडी के लिए 3.68 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया है। जो राज्य सरकार अधिकाधिक वैकल्पिक खाद के प्रयोग को बढ़ावा देकर रासायनिक खाद का प्रयोग काम करेगी उसे बची हुई सब्सिडी की राशि का हिस्सा दी जाएगी। इससे अधिक से अधिक जैविक खाद को प्रोत्साहन मिलेगा। सब्सिडी बचत का 50 प्रतिशत उस राज्य को अनुदान के रूप में दिया जाएगा जो पैसा बचाता है।

योजना के तहत प्रदान किये गए अनुदान का 70 प्रतिशत गाँव, ब्लॉक और ज़िला स्तर पर वैकल्पिक उर्वरकों और वैकल्पिक उर्वरक उत्पादन इकाइयों के तकनीकी अपनाने से संबंधित परिसंपत्ति सृजन के लिये उपयोग किया जा सकता है। शेष 30 प्रतिशत अनुदान राशि का उपयोग किसानों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को पुरस्कृत करने तथा प्रोत्साहित करने के लिये किया जा सकता है जो उर्वरक उपयोग को कम करने व जागरूकता पैदा करने में शामिल हैं। वर्ष 2020-21 में मोदी जी की सरकार ने 1.62 लाख करोड़ रुपए का खाद अनुदान दिया था। और वर्ष 2022 के दौरान यह 2.25 लाख करोड़ रुपए के आँकड़े को पार कर सकता है। अगले तीन वर्षों के लिए मोदी सरकार ने 3.68 लाख का पैकेज घोषित किया है।

केंद्र ने अक्तूबर 2016 से उर्वरकों में डीबीटी की शुरुआत की, जिसके तहत विभिन्न उर्वरक ग्रेड पर उर्वरक कंपनियों को खुदरा विक्रेताओं द्वारा लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर 100 प्रतिशत सब्सिडी जारी की जाती है। इसके अलावा देश भर ने किसान किसान समृद्धि केंद्रो से प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद देंगे छत्तीसगढ़ में ऐसे लगभग 2 हजार केंद्र है किसान सम्मान समृद्धि केंद्रो से किसानों के हित की सारी योजनाओं की बहुत सी जानकारियां प्रदान की जाती है।

कांग्रेस के गढ़ में नहीं हुआ विकास, भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम सौंपा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के कोटा विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। इसके बाद भी आज तक कोटा विधानसभा विकास कार्यों में पिछड़ा हुआ है। इसी को लेकर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर 21 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपा है।

भाजपा कार्यकर्ताओं की मुख्य मांग कोटा नगर के रिहायशी इलाके में संचालित हो रही शराब की दुकान को वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने की है। कोटा रतनपुर राजमार्ग पर पुल टूटे हुए दो महीने हो गए हैं, उसे सही किया जाए। रतनपुर महामाया देवी की नगरी है और यहां श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। पुल टूटने के कारण श्रद्धालुओं को भटकना पड़ता है। राम मंदिर से पंडरा पथरा प्रधानमंत्री सड़क योजना दो साल से जर्जर हालत में है, जिसकी तत्काल मरम्मत करायी जाए।

कोटा रेलवे स्टेशन तक सड़क लोकनिर्माण विभाग की स्वीकृत दो साल से है, जिसे तत्काल प्रारंभ किया जाए। गौरेला पेंड्रा नगर पंचायत को मुख्यमंत्री के द्वारा तीन वर्ष पहले नगर पालिका बनाने की घोषणा की गई थी, जो आज तक अस्तित्व में नहीं आई। इसे शीघ्र पूरा किया जाए। रतनपुर नगर पालिका एवं कोटा नगर पंचायत क्षेत्र में आबादी भूमि पर पट्टा देने के लिए शासन द्वारा सर्वे कराया गया है। आम नागरिकों से शुल्क भी लिया गया और कुछ लोगों को पट्टा देने के बाद पट्टा वितरण बंद कर दिया गया। ऐसे में बाकी आम नागरिकों को पट्टा दिलाया जाए।

तेंदू पत्ते का बोनस पूरे कोटा विधानसभा क्षेत्र में दो वर्षों से नहीं दिया गया, वह शीघ्र दिया जाए। रेत माफियाओं द्वारा अरपा नदी में खुला दोहन किया जा रहा, उस पर रोक लगाई जाए। पूरे क्षेत्र में सड़कों की हालत दयनीय है, जनहित में सड़कों का नवीनीकरण कराया जाए। ग्राम करगिकला में रीपा योजना से करोड़ों रुपये के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसी ही विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर कोटा विधानसभा के छ: मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम सौंपा है।

30 से कांग्रेस का डोर टू डोर अभियान दक्षिण विस का किला भेदने की तैयारी

रायपुर। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने सोमवार को प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के डोर टू डोर अभियान के बारे में जानकारी साझा की। कांग्रेस 30 जुलाई को दक्षिण विधानसभा से इस अभियान की शुरुआत करने जा रही है।

रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने डोर टू डोर अभियान की जानकारी दी हैं। जिसको लेकर सोमवार को कांग्रेस द्वारा बैठक आयोजित की गई थी। रायपुर नगर निगम के कांग्रेसी जनप्रतिनिधि सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाएगी। 30 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज इस अभियान में शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अभियान में होंगे शामिल- इस अभियान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के कार्यकर्ता, पार्षद, बूथ अध्यक्ष, एनएसयूआई समेत सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। इस अभियान की शुरुआत दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से किया जाएगा। एक दिन में एक वार्ड का भ्रमण कांग्रसी करेंगे।

महापौर एजाज ढेबर ने कहा रायपुर नगर निगम की टीम इस अभियान के दौरान नगर निगम संबंधित कोई भी समस्या होगी। तो उसका निदान तत्काल मौके पर ही किया जाएगा।

विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयार- छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है। राजधानी रायपुर के 3 विधानसभा कांग्रेस के कब्जे में है। चौथा दक्षिण विधानसभा भाजपा के कब्जे में है।जहां से भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल विधायक हैं। इस सीट को हथियाने के लिए कांग्रेस दक्षिण विधानसभा से इस अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान का जनता पर कितना असर होगा, यह तो समय ही तय करेगा।

जेल से बाहर निकले मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर, समर्थकों ने पटाखे फोड़े

रायपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रायपुर मेयर के बड़े भाई और शराब कारोबारी अनवर ढेबर को कल देर शाम जेल से रिहा कर दिया गया। इस दौरान उनके स्वागत में समर्थकों का हूजुम उमड़ पड़ा। सेंट्रल जेल में करीब डेढ़ सौ से अधिक समर्थक पहुंचे। ढेबर को फूल माल पहनाई। पटाखे फोड़कर और आतिशबाजी कर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर जेल कैंपस के बाहर नारेबाजी की गई। देखो-देखो कौन आया, शेर आया... के नारे भी लगाए गए।

ढेबर का स्वागत इस अंदाज में किया गया, जैसे कोई विजेता का स्वागत किया जाता है। दो हजार करोड़ के शराब घोटाले मामले में जेल से रिहा होने के बाद समर्थक कई कारों और बाइक में रैली की शक्ल में जेल पहुंचे। अनवर ढेबर को ढोल नगाड़े और आतिशबाजी से स्वागत कर इसी अंदाज में घर लाया गया। इस दौरान रिश्तेदारों और मोहल्लेवासियों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी।

बताया जाता है कि उनकी रिहाई की खबर सुनते ही समर्थक सेंट्रल जेल के बाहर एकत्र होने लगे थे। जब अनवर ढेबर जेल से बाहर निकले तो समर्थकों ने उन्हें गले लगा लिया। शराब कारोबारी ढेबर को ईडी ने 6 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वो ईडी की कस्टडी में रहने के बाद सेंट्रल जेल में बंद थे। ढेबर को जमानत मिलने के बाद अब बाकी आरोपियों (नितेश पुरोहित, त्रिलोक ढिल्लन) को भी जमानत मिलने की आस जग गई है। नितेश पुरोहित और त्रिलोक ढिल्लन कोर्ट में गंभीर बीमारियों का हवाला देकर देने की गुहार लगा चुके हैं पर कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

कारोबारी अनवर ढेबर मामले में सोमावार को बिलसापुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। अनवर ढेबर ने अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। कारोबारी अनवर ढेबर को कोर्ट द्वारा मेडिकल ग्राउंड पर राहत मिली है। यह सुनवाई जस्टिस दीपक तिवारी की सिंगल बेंच में हुई है। बता दें कि कारोबारी अनवर ढेबर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था।

याचिकाकर्ता अनवर ढेबर के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कारोबारी अनवर ढेबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ढेबर को 3 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। ढेबर ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कारोबारी अनवर ढेबर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत याचिका को मंजूर कर ली गई है। हाईकोर्ट में आगामी सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जाएगा।

शासन की योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन में आईएएस अधिकारियों की महती भूमिका: बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल राजधानी के एक निजी होटल में आयोजित आईएएस कॉन्क्लेव 2023 के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान छत्तीसगढ़ में शासन की योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन में आईएएस अधिकारियों की महती भागीदारी का जिक्र करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आगे कहा कि आईएएस अधिकारियों का कार्यक्षेत्र व्यापक और चुनौतीपूर्ण होता है। इसे सही दिशा देने में अधिकारियों को चाहिए कि वे अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ कुशलतापूर्वक करें। एक आईएएस अधिकारी का कार्य हर वर्ग सहित आम जनता से सीधा-सीधा जुड़ा हुआ होता है। इसे ध्यान में रखते हुए जनहित में योजनाओं तथा कार्यक्रमों का बेहतर से बेहतर क्रियान्वयन के लिए हमेशा तत्पर होकर कार्य करें और आम आदमी को उसका अधिक से अधिक लाभ पहुंचाए।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि एक आईएएस अधिकारी की अपने कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण जवाबदेही होती है। इसके लिए सफल दायित्व निर्वहन हेतु अधिकारियों में व्यवहार कुशलता के साथ-साथ संवेदनशीलता की भी स्पष्ट झलक मिलनी चाहिए, जिससे हर जरूरतमंद व्यक्ति अपनी बातों को बेहिचक उनके सामने साफ-साफ रख सके। उन्होंने कहा कि इस तरह छत्तीसगढ़ के विकास और लोगों की उन्नति के लिए आगे भी उनका योगदान तथा महत्वपूर्ण भागीदारी बनी रहे।

समारोह को मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन तथा अध्यक्ष आईएएस एसोसिएशन छत्तीसगढ़ श्री मनोज पिंगुआ ने भी सम्बोधित किया और मुख्यमंत्री श्री बघेल के कुशल मार्गदर्शन के लिए आभार जताया। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू सहित ऐसोसिएशन के पदाधिकारी और राज्य के समस्त आईएएस अधिकारी उपस्थित थे।

सीएम हाउस में 7 घंटे चली हाईलेवल बैठक

रायपुर। रायपुर में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हुई है। मुख्यमंत्री आवास में मंगलवार को खास तौर पर इस बैठक का आयोजन किया गया था, जो करीब 7 घंटे तक चली। कांग्रेस की चुनावी रणनीति और निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा की है। विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है।

इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सेलजा, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, मंत्री रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी इस बैठक में शामिल होने पहुंचे थे।बैठक के बाद देर शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा-प्रदेश अध्यक्ष सहित बाकी नेता बैठक में मौजूद थे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर डिटेल चर्चा हुई है। निगम-मंडल और आयोग में पदाधिकारियों को रिपीट करने या नये को मौके के सवाल पर सीएम ने कहा- समय आने पर पार्टी इसे लेकर निर्णय लेगी।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री पीयूष घोयल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा-घटना किसी भी प्रदेश में घट सकती है। लेकिन उसके बाद सरकार ने निर्णय क्या लिया यह महत्वपूर्ण है। मणिपुर के घटना भाजपा सरकार की नाकामी है। उसे छिपाने के लिए आप कभी राजस्थान का कभी, छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे हैं। इसका मतलब है, आप के दिमाग में केवल चुनाव का कीड़ा कुलबुला रहा है। स्थिति को आप डायवर्ट करने की कोशिश मत करिए, जो गलतियां हैं, उसे स्वीकार करिए।वहीं बैठक के बाद ही डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी पत्रकारों से चर्चा की। द्ब्रष्ठढ्ढ को लेकर पीएम मोदी के दिए बयान पर टीएस सिंहदेव ने कहा-ये छद्म मानसिकता का परिचायक है। देश की आजादी के बाद अनेकों विद्वानों ने असेंबली के माध्यम से संविधान बनाया। उसका शब्द क्या है भारत थैट इज इंडिया। जब इंडिया हमारे संविधान में वो स्थान रखता है। आप उसके बारे में बोल रहे है देशद्रोह का मामला बनता है कि नहीं बनता है। हमारे संविधान में जो बात लिखी है, आप उसको नकार रहे हैं।उन्होंने कहा कि कैसे प्रधानमंत्री हमारे देश में हैं। कैसी सत्तापक्ष देश में बैठी हुई है। यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। इसको संज्ञान में लेना चाहिए। अगर कोई और नहीं लेता है तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए।कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, एक दिन पहले कांग्रेस भवन में बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी सेलजा ने साफ कह दिया था कि निगम मंडल में नियुक्तियों के लिए नए लोगों को मौका दिया जाएगा।

अमित जोगी का भूपेश सरकार पर हमला

रायपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी छ्वष्टष्टछ्व प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने भूपेश सरकार पर माइनिंग टेंडर को लेकर निशाना साधा है। अमित जोगी ने प्रदेश की कुछ खदानों को निजी कंपनियों को देने का दावा किया। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हीरे और सोने की खदानों को प्राइवेट हाथों में दिए जाने का आरोप लगाया है। अमित जोगी का दावा है कि चुनाव से पहले टेंडर निकाले गए हैं। 6 जुलाई को एक टेंडर निकाला गया है। 3000 हेक्टेयर जमीन में माइनिंग शामिल है। गरियाबंद से मैनपुर में पांच माइनिंग ब्लॉक है, जिसमें सोने हीरे की खदान हैं। अगर 3 दिन के अंदर टेंडर निरस्त नहीं किया जाएगा तो पूरे प्रदेश में ऐसा आंदोलन करेंगे ,जिसे लेकर अब तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अमित जोगी ने कहा कि चुनाव को 3 महीने बचे हैं। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला, शराब घोटाला, रेत घोटाला हो रहा है। अब हीरे और सोने की खदानों पर भी वसूली की जा रही है। कोल माइनिंग मामले में पहले से ही ईडी की टीम जांच कर रही है। ईडी एक सक्षम एजेंसी है। उनको यह जांच करनी चाहिए कि जो अधिकारी और नेता ऑस्ट्रेलिया ,नीदरलैंड,दुबई, जा रहे हैं, वह छत्तीसगढ़ का आखिर क्या भला कर रहे हैं।

मैं सरकार के मुखिया से सीधा टकरा रहा हूं डरने वाला नहीं:मूणत

रायपुर। पश्चिम विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता के हुजूम का नेतृत्व करते हुए पूर्व मंत्री राजेश मूणत कलेक्टर कार्यालय में हल्ला बोल करने वा घेराव करने पहुंचे लगभग 5000 की संख्या में रायपुर पश्चिम की जनता मूणत के साथ विभिन्न मांगो का ज्ञापन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची सभी के हाथो में सरकार की नकामिया लिखी हुई तख्तियां , भाजपा के झंडे थे सड़को पर नारेबाजी के साथ पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे परन्तु उसी समय राजेश मूणत का गुस्सा तब फूट पड़ा जब समय देने के बावजूद रायपुर कलेक्टर ज्ञापन लेने नही पहुंचे और पुलिस प्रशासन का रवैया कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त हो गया मूणत ने पुलिस प्रशासन को ऐसा करने मना किया और ए.एस.पी. को जमकर आड़े हाथ लिया उन्होंने कहा की वर्षो से जनप्रतिनिधि रहा हूं जनता की समस्याओं की लड़ाई सड़क पर उतर के लड़ते आ रहा हूं आपका रवैया गैरजिम्मेदाराना है चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन जनता की आवाज बनता रहूंगा शासन प्रशासन की गीदड़भभकियो

से डरने वालों में से राजेश मूणत नही उन्होंने कहा की हम रायपुर कलेक्टर को जनसमस्याओं का ज्ञापन देने आए है और कलेक्टर की निरसता इतनी अधिक है की जनसमस्याओं से उन्हें कोई लेना देना नही पहले भी हमारा नेतृत्व जिला अध्यक्ष जयंती पटेल सहित ज्ञापन देने पहुंचा लेकिन कलेक्टर के पास समय ही नहीं था , पुलिस प्रशासन शासन के इशारों पर हमारे द्वारा जनसमस्याओं के निराकरण के लिए किए जा रहे आंदोलनों का दमन करने का प्रयास किया जा रहा है जिस प्रशासन को शहर में बढ़ते अपराध , नशे के कारोबार को रोकने में असमर्थ पुलिस जनप्रतिनिधियों को रोकने में मेहनत कर रही है हम जनता के लिए लड़ने से किसी से नही डरते ना ही शासन से और ना ही प्रशासन से

मैं प्रदेश सरकार के मुखिया से सीधा टकरा रहा हूं मुझे किसि का कोई भय नहीं चाहे जो करना है कर ले ये राजेश मूणत जनता की समस्याओं के लिए सड़क की लड़ाई लड़ता रहेगा जिस प्रदेश का मुखिया स्वयं तमाम भ्रष्टाचारों में सहभागी हो वह जनता के हितों का ख्याल कतई नहीं रख सकता और ऐसे कर्तव्य विमुख मुखिया से हम नही डरते चाहे हमे डराने के कोई भी हथकंडे लगा लिए जाएं हम यहां आए तो इसलिए थे की रायपुर पश्चिम में व्याप्त अनगिनत समस्यायों के निराकरण की मांग कलेक्टर के पास ज्ञापन सहित रखेंगे लेकिन अब हम बिना ज्ञापन दिए ही लौट रहे हैं मैं सीधा आरोप लगाता हूं की प्रदेश कांग्रेस सरकार , स्थानीय विधायक और कलेक्टर के लिए जनसमस्याओं से जुड़ा ज्ञापन रद्दी मात्र है जिसमे कोई सुनवाई नहीं होती और उसे सीधा रद्दी कागज समझ कर फेंक दिया जाता है हमने विगत दिनों भी बहुत से ज्ञापन दिए लेकिन किसी एक में भी सुनवाई नहीं हुई तो अब क्या होगी हम अब यह ज्ञापन हम कोरियर माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को भेजेंगे और उनसे मांग रखेंगे । आज प्रदेश की जनता प्रदेश सरकार की नाकामियों से त्रस्त है जनसमस्याओं के निराकरण का टोटा है प्रदेश सरकार और उसके नुमाइंदे जनता मांगो के निराकरण में नकारा साबित हुई है जब जनता की कोई नही सुनता तो हताश होकर वह अन्य जनप्रतिनिधियों के पास जाती है ऐसे में हमारा कर्तव्य है जनता की आवाज बनना आज हमारा सीधा सवाल पश्चिम विधायक और कांग्रेस सरकार से है की। रायपुर भाजपा शहर जिला अध्यक्ष जयंती पटेल ने कहा की हम लगातार कांग्रेस सरकार और उसके विधायकों के खिलाफ आंदोलनरत है पूर्व में रायपुर उत्तर , ग्रामीण और दक्षिण के भाजपा नेताओ द्वारा आंदोलन किया गया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने गए लेकिन उनके पास समय नहीं था कलेक्टर दायित्व विमुख होकर कार्य कर रहे है यह दुखदाई है सरकार तो वैसे ही जनता की सस्याओ पर धृतराष्ट्र बन चुकी है अब यदि जिला के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी भी दायित्वों से पलड़ा झड़ेंगे तो जनता कहाँ जायेगी किसका दरवाजा खटखटाएगी ।

पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी , केदारनाथ गुप्ता , संजय श्रीवास्तव , मोतीलाल साहू , ओंकार बैस , राजीव कुमार अग्रवाल , मीनल चौबे , छगन मूंदड़ा , गोवर्धन खंडेलवाल प्रफुल्ल विश्वकर्मा , प्रभा दुबे महामंत्री द्रय सत्यम दुवा , रमेश सिंह ठाकुर , आशु चंद्रवंशी , शैलेंद्र परघनिया , मनीषा चंद्राकर , गोपी साहू , अमित मैशरी , तुषार चोपड़ा , सीमा संतोष साहू ,शिवजलम दुबे , बजरंग खंडेलवाल , अमरजीत छाबड़ा , सोनू वालिया , अखिलेश कश्यप , पुष्पेंद्र , गोविंदा गुप्ता , नीलम सिंह , अनिल सोनकर , प्रीतम ठाकुर , बी.श्रीनिवास राव , भूपेंद्र ठाकुर , विनोद अग्रवाल ,भोला साहू , मृत्युंजय दुबे , राजियत ध्वव , दीपक जयसवाल , राजेश ठाकुर ,कमलेश वर्मा , कामिनी पुरषोत्तम देवांगन , गोदावरी गज्जू साहू , सुनील चंद्राकर , राहुल राव , अर्पित सूर्यवंशी , विशेष शाह , सुरेंद्र साहू , विनय जैन , दीपू शर्मा , शरद राठौर सहित हजारों कार्यकर्ता एवं पश्चिम की स्थानीय जनता अपनी मांगो को लेकर कलेक्ट्रेट घेराव करने पहुंची ।

विभिन्न मांगो को लेकर ज्ञापन सौंपने गए थे मूणत

- पक्की छत का सपना देखने वाले 16 लाख परिवारों के साथ न्याय कब?
- केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक गरीब परिवार के लिए 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज भेजा गया था जिसमे 62 हजार मैट्रिक टन का कोई हिसाब नही 5 हजार करोड़ से अधिक की गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच कब?
- गंगाजल हाथ में लेकर माताओं बहनों से शराबबंदी का वादा करने वालो ने आज रायपुर पश्चिम में जगह जगह अहाते खुलवा कर क्षेत्र का वातावरण बिगाड़ दिया है उसका निराकरण कब?
- संपत्ति कर हाफ का झूठा वादा पूरा होगा कब?
- वृद्धा पेंशन बंद कर वृद्धों के साथ छल ,
- गोबर के नाम पर सैकड़ो करोड़ रुपयों के घोटाले की जांच कब?
- रायपुर शहर को खोदापुर बना दिया गया है जगह जगह गड्ढों का अंबार है लेकिन सरकार उसका दुरुस्तिकरण करेगी कब?
- रायपुर सहित पूरे प्रदेश को अपराधगढ़ बना दिया गया है जो मेहनत प्रशासन सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने में लगाती है यदि उसे अपराधियों पर शिकंजा कसने में लगाते तो शायद प्रदेश की स्थिति इतनी बुरी नही होती अपराधियों पर शिकंजा कब?
- रायपुर को नशे का हब बना दिया गया है लेकिन कार्यवाही कब?

प्रांतीय अखंड ब्राह्मण समाज का सावन उत्सव आयोजित

रायपुर, मंगलवार - दिनाँक 25 जुलाई 2023। प्रांतीय अखंड ब्राम्हण समाज संगठन द्वारा सावन उत्सव का आयोजन सुंदर नगर में किया गया। प्रदेश अध्यक्ष भारती किरण शर्मा ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। प्रदेश सांस्कृतिक सचिव शजिन्ता शुक्ल द्वारा सावन के ऊपर बहुत ही रोचक सावन तम्बोला खेल खिलाया गया- जिसमें बादल बरस गया.., टिप टिप बरसा पानी.., काली घटा छा गई.. आदि नामों पर विजेता प्रथम हेमलता शुक्ला द्वितीय सरिता शर्मा तृतीय रानी दुबे घोषित किए गए। सावन से संबंधित शब्दों वाले खेल में अत्यधिक आनंद लिए जिसमें, प्रथम रहीं सुनीता बीनु मिश्रा, द्वितीय सुषमा कौशलेंद्र शुक्ला, तृतीय प्रीति शुक्ला।

मनभावन सावन माह में शिवभक्त माता सती को प्रकृति के रूप में समझाने का सन्देश दिया। इसे आल्हादित प्रेम में ओतप्रोत हो कर स्त्रीत्व को प्रकृतिवादी पर्यावरणीय प्रेम का सामूहिक आयोजन कहना ही उचित है। मातृ शक्ति के अप्रतिम प्रेम की अभिव्यक्ति सावन झूले सामूहिक आनंद से हुई। तीसरे खेल बारह महीने के मुख्य त्योहारों के नाम% में- प्रथम रीता शर्मा, द्वितीय प्रीति शुक्ला, तथा तृतीय रोशनी शुक्ला रहीं। सावन उत्सव की समाप्ति वंदे मातरम गीत के द्वारा हुई।

भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने की छत्तीसगढ़ में स्वीप कार्यक्रमों की समीक्षा

रायपुर। आगामी विधानसभा आम निवार्चन के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में संचालित स्वीप कार्यक्रमों की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा में आयोजित दो दिवसीय समीक्षा-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम में आयोग के अधिकारियों ने सभी जिलों में मतदाताओं को जागरूक करने चलाई जा रही गतिविधियों की समीक्षा की और उप जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-जिला स्तरीय स्वीप नोडल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। भारत निर्वाचन आयोग में स्वीप के संचालक श्री संतोष अजमेरा, सचिव श्री संतोष कुमार, स्वीप के वरिष्ठ सलाहकार श्री आर.के. सिंह और सुश्री रजनी उपाध्याय राज्य में स्वीप गतिविधियों की समीक्षा के लिए दो दिनों के प्रवास पर रायपुर आए हुए हैं।

भारत निर्वाचन आयोग में स्वीप के संचालक श्री संतोष अजमेरा ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन के लिए आयोग निर्वाचन की हर गतिविधियों को गंभीरता से संचालित करती है। त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली से सुचारू मतदान में मदद मिलती है।

महिलाओं को आजीविका से जोड़कर सक्षम बनाने हुआ शिखर सम्मेलन

रायपुर। राजधानी रायपुर में कृषि विभाग समर्थित, ग्रांट थॉर्नटन भारत एलएलपी और सोसाएटी फॉर डेव्हलपमेंट अल्टरनेटिव्स द्वारा एचडीएफसी बैंक परिवर्तन कार्यक्रम के तहत 'छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका शिखर सम्मेलन 2023' का आयोजन किया गया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने में शामिल प्रमुख हितधारकों के बीच ज्ञान और अनुभव साझा करने के लिए मंच प्रदान करना था, जिसमें किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), सरकारी पहल और पारिस्थितिकी तंत्र विकास पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही महिलाओं के लिए आजीविका के विकास और संबंधित एफपीओ की स्थिरता के लिए एक सक्षम वातावरण विकसित करने के लिए एक रणनीति पर विचार-विमर्श करना भी एक प्रमुख उद्देश्य था।

वक्ताओं और विशेषज्ञों ने छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे अन्य राज्यों में एफपीओ पारिस्थितिकी तंत्र में अमूल्य अनुभव को साझा किया। इन सभी हितधारकों को एक साथ आने और प्रासंगिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने और नीतियों के लिए अन्य सुझावों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया।

एचडीएफसी बैंक ने अपनी सीएसआर के तहत पूरे भारत में व्यक्तियों की आजीविका में सुधार के लिए कई पहल की है। एचडीएफसी बैंक, विशेष रूप से ऑन-फार्म, ऑफ-फार्म और गैर-फार्म के माध्यम से किसानों, महिलाओं और युवाओं की आजीविका हस्तक्षेप के सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

मोदी प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरा रहे है: दीपक बैज

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त विपक्ष के गठबंधन इंडिया की तुलना आतंकी संगठनों से किये जाने की कांग्रेस ने कड़ी निंदा किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य देश के

लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। मोदी ने विपक्ष के बारे में ऐसा बयान देकर प्रधानमंत्री की गरिमा को गिराया है। प्रधानमंत्री विपक्ष की एकता से घबराये हुये है तथा गलत बयानी कर अपनी कुंठा को बाहर निकाल रहे है। प्रधानमंत्री के अंदर का डर उनसे गलत बयानी करवा रही है।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि देश की जनता मोदी सरकार की वायदा खिलाफी कुशासन से मुक्ति के लिये 2024 के चुनाव का इंतजार कर रही है। मोदी झूठ बोलकर विपक्ष पर अनर्गल आरोप लगा कर अपनी असफलता से जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं देश का किसान, नौजवान, आम आदमी, गृहणी सभी मोदी सरकार से परेशान है। 100 दिन में महंगाई कम करने की बड़ी-बड़ी बाते करने वाले मोदी के राज में महांगई चरम पर है। दाल, तेल, आटा, टमाटर सभी के दाम आसमान छू रहे। पेट्रोल-डीजल मोदी सरकार की वसूली के माध्यम बन गये है। चुनाव के पहले 35 रू. लीटर में डीजल-पेट्रोल देने का वायदा करने वाली भाजपा 35 रू. लीटर एक्साइज वसूल रही है। मोदी कुछ भी कर ले उनकी विदाई तय है।

सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, हम कोर्ट जाएंगे : मरकाम

रायपुर। कोयला घोटला में गिरफ्तार आईएएस रानू साहू को कोर्ट ने 10 दिन के लिए ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया कोर्ट ने रानू साहू को अब 4 अगस्त को पेश करने का आदेश दिया है। ईडी ने शुक्रवार को देवेंद्र नगर स्थित रानू साहू के सरकारी

आवास पर छापा मारा था। करीब चौबीस घंटे की जांच के बाद ईडी ने शनिवार सुबह उन्हें गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश कर 14 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने केवल तीन दिन की ही रिमांड मंजूर की थी। रिमांड की अवधि पूरी होने पर मंगलवार दोपहर बाद ईडी ने उन्हें विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में पेश किया। ईडी की तरफ से फिर से रिमांड की मांग नहीं की गई। इसकी वजह से कोर्ट ने रानू साहू को सीधे जेल दाखिल करने का आदेश दिया। छत्तीसगढ़ में राजनेताओं, आईएएस और प्रशासनिक अफसरों के साथ सप्लायरों पर लगातार ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की कार्रवाई जारी है। अब आईएएस रानू साहू की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से आदिम जाति कल्याण मंत्री मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मोहन मरकाम ने कहा कि, मोदी सरकार के कार्यकाल में जहां विपक्ष की सरकार है, उन्हीं राज्यों में ईडी की कार्रवाई हो रही है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम न्यायालय जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। आदिम जाति कल्याण मंत्री मोहन मरकाम मंगलवार को अंबिकापुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने विभाग की संभागीय समीक्षा बैठक ली।

भाजपा अशांति फैलाने का षडयंत्र रच रही : शुक्ला

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अशांति फैलाने का षडयंत्र रच रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री ने मणिपुर से छत्तीसगढ़ की तुलना की, केन्द्रीय मंत्री पियुष गोयल ने छत्तीसगढ़ की तुलना मणिपुर से की

और भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ का एक नेता ने मणिपुर के बाद अब छत्तीसगढ़ का नंबर सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अशांति फैलाने के लिये कुछ न कुछ षडयंत्र रच रही है। आखिर छत्तीसगढ़ मणिपुर की साम्यता क्या है? मणिपुर में 50 हजार से अधिक लोग विस्थापित हो गये है। 5000 से अधिक घरो को जला दिया गया है। 100 से अधिक लोग मर गये है। माताये-बहनों को वहां नग्न करके घुमाया जा रहा है। ऐसे अशांत प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा छत्तीसगढ़ की तुलना किया जाना भाजपा के बड़े षडयंत्र की ओर इशारा कर रह मुद्दाविहीन भाजपा निचले स्तर की राजनीति पर उतर आई है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद महिलाओं के जीवन जीने के लिये अपराधमुक्त सुरक्षित वातावरण तैयार हुआ है।

रमन सरकार में फिल्मी सितारों पर करोड़ो लुटाये थे: धनंजय

रायपुर। भाजपा प्रवक्ता एवं विधायक अजय चंद्राकर के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार राम नाम पर खर्च कर रही है। पूर्व रमन सरकार में करीना कपूर और सलमान खान के ऊपर करोड़ो लुटाये और उड़ाये थे

तब अजय चंद्राकर को मजा आ रहा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार राम नाम पर खर्च कर रही है, राम काज कर रही है, राम का गुणगान कर रही है तो भाजपाइयों को गड़बड़िया दिख हो रही हैं। असल मे भाजपा नेताओ के दिमाग मे केमिकल लोचा हो गया इन्हें किसी मनोचिकित्सक से ईलाज करवाना चाहिये। 15 साल में भाजपा की सरकार ने खाली भ्रष्टाचार ही तो किया है। सत्ता जाने के बाद भी कमीशनखोरी की गंदगी इनके दिमाग में बैठी है। इसलिए इन्हें अब राम नाम पर हुई खर्च में भी घोटाला दिख रहा है। आखिर भाजपा को राम नाम से राम नाम के गुणगान से इतनी नफरत क्यों है? भाजपा के नेता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से चंदा लेते हैं वोट लेते हैं लेकिन राम काज नहीं करते हैं ना ही मर्यादा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ के भाषा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के वनवास काल में छत्तीसगढ़ में व्यतीत किये गये पलो को आकार दिया। श्री राम जी के पग जिन मार्गो पर पड़ा था जिन स्थानों में श्री राम जी रुके थे उन सभी पूज्यनीय स्थलों को राम वन गमन पथ के रूप में विकसित किया।

1 से 13 अगस्त तक जिले में होगा वजन त्यौहार

रायपुर । जिले में प्रदेशव्यापी वजन त्यौहार के अंतर्गत 1 से 13 अगस्त तक सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में वजन त्यौहार मनाया जाएगा। इसमें 0 से 06 वर्ष तक सभी बच्चों का वजन लेकर कुपोषण की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाएगा। 0 से 06 वर्ष के सभी बच्चों का वजन क्लस्टरवार तिथि का निर्धारण करते हुए क्लस्टर के चिन्हांकित आंगनबाड़ी केन्द्रो में किया जाएगा। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने सभी पालकों से आंगनबाड़ी केन्द्र जाकर वजन कराने का आग्रह किया है। इस आयोजन के माध्यम से कुपोषण की स्थिति का सही आकलन होगा और कुपोषण कम करने के लिए जन जागरूकता लाई जाएगी और कार्ययोजना भी बनाई जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्र में दर्ज बच्चों के अलावा वजन त्यौहार आयोजन के समय बाहर से आए बच्चे भी वजन लेने से वंचित न रहे यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। वजन त्यौहार के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों में 6 वर्ष से कम आयु बच्चों के पोषण स्तर का आकलन के साथ ही बच्चों की नि:शक्तता की स्थिति के बारे में जानकारी ली जाएगी। इससे स्थान विशेष और वर्गों में कुपोषण की पहचान होगी और किन स्थानों पर, किन कारणों से कुपोषण अधिक है यह स्पष्ट हो सकेगा। इससे उस स्थान या वर्ग के लिए विशेष योजना बनाई जा सकेगी। बच्चों के पोषण स्तर के बारे में अभिभावकों को अवगत कराते हुए उन्हें कुपोषण के संबंध में जागरूक कर, बच्चों को कुपोषण से बाहर लाने हेतु उचित परामर्श दिया जाएगा।

जन आक्रोश रैली: वादाखिलाफी के विरोध में सड़क पर भाजपाई

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में मंगलवार को भाजपाइयों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सरकार पर वादाखिलाफी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। इस दौरान कलेक्ट्रेट का घेराव करने बढ़ रहे कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिया। जिसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई है। प्रदर्शन और रैली में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह समेत तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए हैं। इसे जन आक्रोश रैली का नाम दिया।

दरअसल, राजनांदगांव की तमाम समस्याओं और राज्य सरकार की वादाखिलाफी को लेकर भाजपा कार्यकर्ता ने महावीर चौक पर धरना दिया। इसके बाद कार्यकर्ता रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकल पड़े। रैली महावीर चौक से

गुरुनानक चौक होते हुए प्यारेलाल चौक पहुंची। वहां पर पहले से ही उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी और पुलिस फोर्स तैनात थी। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ने लगे। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।

राजनांदगांव के साथ हुआ अन्याय

पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि, राज्य सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ की सभी विधानसभा में प्रदर्शन और घेराव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि, राजनांदगांव के साथ अन्याय हुआ है। सारी सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। यहां तक मेडिकल कॉलेज की हालत यह हो गई कि ना सीटी स्कैन मशीन है, ना एमआरआई मशीन है और ना ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम है। पूरी तरह हालत बेहाल हैं। रेत माफिया और शराब माफिया प्रदेश भर में सक्रिय हैं। रेत की अवैध निकासी इतनी बढ़ गई है कि तस्करी के साथ-साथ अब शव भी मिल रहे हैं।अब रेत के साथ शव भी बेचा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार भाजपा के बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने जवाब दिया है।

छत्तीसगढ़ राजभवन में लगी कुलपतियों की दरबार

रायपुर। आज के युवा हमारे भविष्य हैं। आने वाली कल की जिम्मेदारी उन पर है। इसलिए वे विश्वविद्यालय की गतिविधियों तक सीमित ना रहें बल्कि आम नागरिकों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझे और जिम्मेदार नागरिक बनकर अपनी भूमिका का निर्वहन करें। विद्यार्थियों को संवेदनशील एवं देश भक्त नागरिक बनाने के लिए विश्वविद्यालयों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सभी को मिल कर विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए ताकि आत्मनिर्भर भारत की ओर हम अग्रसर हो सके।

राजभवन में राज्य के सभी 15 शासकीय विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों, अनुसंधान कार्य एवं अन्य

कार्यो की समीक्षा के दौरान उक्त बातें कही। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, राज्यपाल के सचिव श्री अमृत खलखो, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमल प्रीत सिंह, अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं सभी शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे।

बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की स्थिति, नैक द्वारा विश्वविद्यालयों एवं संबंद्ध महाविद्यालयों के मूल्यांकन की स्थिति, ग्रेडिंग और संस्थानों द्वारा नेक ग्रेडिंग सुधारने के लिए किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई। बैठक में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के मध्य हुए एम.ओ.यू., अकादमिक सत्र के पालन, परीक्षाओं एवं परिणाम के समय पर जारी करने के संबंध में एवं विश्वविद्यालयों द्वारा कराए गए विशेष अनुसंधान, नवाचार आदि की भी जानकारी ली गई।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.